राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट
और
अंकेक्षित वित्तीय विवरण
(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

वित्तीय वर्ष 2018-19

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(NICDIT)

INDEX

FINANCIAL YEAR 2018-19

S. No.	Particulars	Page No.
	Hindi	
1	Performa to be attached to O.M. forwarding papers to be laid on the table of both the houses of the Parliament.	1
2	Statement Explaining Reasons for Delay in Laying of Annual Report and Annual Accounts on the Table of both the Houses of Parliament	2 - 3
3	Annual Report	4 - 26
4	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India certifying the Annual Account for the financial year 2018-19	27 - 31
5	Certified Annual Accounts for the financial year 2018-19	32-45
	English	
1	Performa to be attached to O.M. forwarding papers to be laid on the table of both the houses of the Parliament	46
2	Statement Explaining Reasons for Delay in Laying of Annual Report and Annual Accounts on the Table of both the Houses of Parliament	47
3	Annual Report	48 - 62
4	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India certifying the Annual Account for the financial year 2018-19	63 - 67
5	Certified Annual Accounts for the financial year 2018-19	68 - 79

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.क़.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी		
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है	न्यास		
2	संगठन की स्थापना का वर्ष	2012		
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)		
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	न्यास विलेख तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017		
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न हैं)		
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर		
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक		
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे)	हाँ		
9	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	वित्तीय वर्ष	लोकसभा	राज्यसभा
		2015-16	10.04.2017	05.04.2017
		2016-17	02.04.2018	28.03.2018
		2017-18	17.07.2019	26.07.2019
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	लागू नहीं		

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में देरी के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण:

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड) की स्थापना ट्रस्ट डीड के निष्पादन के माध्यम से 27 सितंबर 2012,को की गई थी। ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा एनआईसीडीआईटी के खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी।

एनआईसीडीआईटी के वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुमोदित वार्षिक खातों को संकल्प की प्रति के साथ दिनांक 11 सितंबर, 2019 के पत्र द्वारा, लेखा परीक्षा करने के लिए सीएंडएजी कार्यालय में भेजा गया।

10.10.2019 से 18.10.2019 की अवधि के दौरान, सीएंडएजी कार्यालय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा टीम द्वारा लेखा परीक्षा की गई। लेखा परीक्षा के दौरान और बाद में लेखा परीक्षा टीम को आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए। लेखा परीक्षा टीम द्वारा जारी किए गए हाफ-मार्जिन (एचएम) पर प्रबंधन के जवाब 7 नवंबर, 2019 को पत्र द्वारा सीएंडएजी कार्यालय को भेजे गए। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीडीआईटी के वार्षिक खातों पर ड्राफ्ट सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) सीएंडएजी कार्यालय के पत्र संख्या पीडीसीए/एनडी/सीएचक्यू-II/27-17/2019-20/1143 दिनांक 19 दिसंबर, 2019 द्वारा जारी की गई थी। ड्राफ्ट एसएआर का जवाब सीएंडएजी कार्यालय को 10 जनवरी, 2020 को प्रेषित किया गया था।

चूंकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एनआईसीडीआईटी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की मेज पर नहीं रखा जा सका, इसलिए एनआईसीडीआईटी के पत्र दिनांक 20 नवंबर, 2019 के द्वारा समय बढ़ाने की मांग के लिए एक अनुरोध किया गया था जिसे बजट सत्र के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी ।

सीएंडएजी द्वारा पृथक् ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) 13 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई और आवश्यकतानुसार, संसद के पटल पर इसे रखने से पहले इसे एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जाना आवश्यक है।

31 मार्च, 2020 को निर्धारित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक कोविड महामारी और उसके बाद लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। अंत में, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 19 अगस्त, 2020 को आयोजित की जा सकी, जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने सीएंडएजी द्वारा जारी पृथक् ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) पर विचार किया।

उपरोक्त कारणों के आधार पर, डीपीआईआईटी के माध्यम से समय बढ़ाने की मांग के लिए एक अनुरोध किया गया, जो अतिरिक्त निदेशक, राज्यसभा सचिवालय के ओ.म. दिनांक 1 जुलाई, 2020 द्वारा राज्य सभा के अगले (252) सत्र, 2020 तक प्रदान किया गया।

उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एनआईसीडीआईटी के वार्षिक खातों को संसद के पटल पर नहीं रखा जा सका।

वार्षिक रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2018-19)

भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार दिनांक 15 सितंबर, 2011 को ट्रस्ट डीड के निष्पादन द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2012 को डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड निगमित किया गया था।

भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2016 के आदेश द्वारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के अधिदेश और दायरे को विस्तारित करने तथा देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित करने के लिए अनुमोदन दिया। एनआईसीडीआईटी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। सरकार ने निम्नलिखित संरचना के साथ एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल संरचना के गठन को भी अनुमोदन दिया है:

1. सचिव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष;
2. सचिव, व्यय विभाग, सदस्य;
3. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य;
4. सचिव, सड़क यातायात एवं राजमार्ग, सदस्य;
5. सचिव, जहाजरानी, सदस्य;
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य;
7. सीईओ, नीति आयोग, सदस्य; और
8. सीईओ, एनआईसीडीआईटी, सदस्य सचिव

एनआईसीडीआईटी की भूमिका तथा कार्य निम्नानुसार हैं:

क) औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एक सक्षम संस्थानिक, वित्तपोषण और परिचालनिक ढांचे को स्थापित करना;

ख) औद्योगिक गलियारों, नोडों, अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट और स्टैंडअलोन प्रोजेक्टों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

ग) सभी प्रोजेक्टों का मूल्यांकन करना और एसपीवी को इक्विटी अथवा ऋण अथवा दोनों और वित्तीय शक्तियों के अनुमोदित प्रत्यायोजन के अनुसार परियोजना विकास के लिए अनुदान की स्वीकृति;

घ) नॉलिज पार्टनर(रों), विशेष प्रयोज्य योजनाओं (एसपीवी) और राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक गलियारों में परियोजना विकास गतिविधियों को सहारा देना और उद्योगों के लिए प्रमुख निवेशकों की पहचान करने में राज्यों की सहायता करना;

ङ) आवश्यकता के अनुसार ऋण/इक्विटी जारी करना, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाना;

च) पिछले अनुच्छेदों में उल्लेखित तौर-तरीकों को प्रभावी रूप देने के लिए, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार, राज्य सरकारों/परियोजना विशेष योजनाओं/सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों के साथ कार्य करना;

छ) विशेष रूप से पहचाने गए अर्ली बर्ड प्रोजेक्टों जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर विकसित किया जा सकता है, ऐसे प्रोजेक्टों के लिए राज्यों के मौजूदा तंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध कराना। बहरहाल, शहर/नोड के लिए भूमि आवश्यक रूप से राज्य की इक्विटी होगी और राज्य द्वारा अधिगृहित की जाएगी और उनके द्वारा पूर्णत: भुगतान किया जाएगा।

एनआईसीडीआईटी का संस्थानिक ढांचा निम्नानुसार है:

क. एनआईसीडीआईटी का निदेशक मंडल प्रत्येक एसपीवी की अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि अधिग्रहण और कार्य के वास्तविक निष्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, ऋण और इक्विटी के इष्टतम मिश्रण, वित्तीय साधनों के विकल्प, निधियों की मात्रा, नियम एवं शर्तें और भारत सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान से भुगतान कार्यक्रम को अनुमोदित और स्वीकृति देगा।

ख. एनआईसीडीआईटी औद्योगिक गलियारों के विकास को सक्षम बनाने के लिए यथोचित अनुमोदनों को प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण जुटाने और इसके अतिरिक्त, ऋण मुक्त बांड, कैपिटल गेन बांड, साख संवर्धन आदि जुटाने के लिए भारत सरकार के उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाएगी।

ग. एनआईसीडीआईटी भारत सरकार के अंशदान का परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग करेगा। भारत सरकार द्वारा एसपीवी में किया गया निवेश एनआईसीडीआईटी के माध्यम से होगा ताकि भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का प्रयोग कर डीएमआईसीडीसी द्वारा अभी तक विकसित एसपीवी सहित एसपीवी के सभी ऋण भुगतान और एसपीवी से इक्विटी विनिवेश की प्रक्रिया से प्राप्त धन को परिक्रामी निधि में पुन: लगाया जाए, जो एनआईसीडीआईटी को भविष्य में इस प्रकार के औद्योगिक गलियारे विकसित करने में सक्षम बनाएगा। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी भारत सरकार/राज्य सरकारों से उचित गारंटियों द्वारा साख संवर्धन के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण जुटा सके, ताकि यह बीमा और पेंशन निधियों द्वारा निवेश के लिए अर्थक्षम हो। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी को नवप्रवर्तन अवसंरचना वित्तपोषण शामिल करने और यूजर फी फंडिंग, मूल्य नवप्रवर्तन और विभिन्न पीपीपी व्यवस्थाओं द्वारा भुगतान जैसे भुगतान साधनों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार/एस पी वी द्वारा ऋण के रूप में उठाए गए धन या अन्यथा को भी राज्य की और से योगदान गिना जायेगा ।

घ. पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन देने, उन्हें मूर्त रूप देने, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना प्रोजेक्टों के अनुसार प्रचलित दिशा-निदेशों का अनुपालन किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाएं प्रचलित नीति के अनुसार वॉयाबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की पात्र होंगी। सचिव, डीआईपीपी और सदस्य-सचिव, एनआईसीडीआईटी औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) के सदस्य होंगे। मास्टर प्लान/विकास योजना के अनुसार समन्वित विकास सुनिश्चित करने के संबंध में औद्योगिक गलियारों में वीजीएफ के लिए सभी प्रस्तावों को एनआईसीडीआईटी द्वारा जांचा और अनुशंसित किया जाएगा।

ङ. प्रत्येक इंडस्ट्रियल सिटी/नोड को भारत सरकार से औसतन 2500 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा जो भौगोलिक स्थान, आकार, राज्य के योगदान और विकासात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अधिकतम 3000 करोड़ रुपए होगा। प्रत्येक शहर/नोड के लिए वास्तविक आवश्यकता भिन्न-भिन्न हो सकती है, जो भूमि की लागत और

अवसंरचना विकास तथा भूमि प्रापण/लैंड पूलिंग के लिए धन जुटाने की राज्य सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार का योगदान भूमि अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तपोषण सहित किसी भी स्रोत से उसके द्वारा जुटाए गए धन के रूप में होगा। यद्यपि गैर-पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रति शहर कुल आवश्यकता बहुत अधिक हो सकती है और यह शहर प्रति शहर भिन्न होगी, भारत सरकार से मांगी जा रही उपरोक्त उल्लेखित धनराशि इन शहरों/नोडों में विकास के प्रथम चरण को शुरू करने के लिए है। बाद में, धनराशि आंतरिक मुद्रीकरण द्वारा जुटाई जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

एनआईसीडीआईटी अपने सम्मुख प्रस्तुत सभी गैर-पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। एनआईसीडीआईटी बोर्ड किए गए मूल्यांकन के आधार पर, यह 300 करोड़ रुपए तक की मूल्यांकित परियोजनाओं का अनुमोदन देगा। 300 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ तक की मूल्यांकित परियोजनाओं के मामले में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 500 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए से से अधिक सभी प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान, न्यास मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है।

डीएमआईसी नोड की योजना और उनकी अपनाई गई संधारणीयता विशेषताएं:

विकसित किए जा रहे डीएमआईसी नोड्स एक लंबे समय तक चलने वाले दृष्टिकोण को अपनाते है जो खुले हरित क्षेत्रों, पब्लिक ट्रांजिट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, पारंपरिक ऊर्जा के प्रयोग को न्यूनतम करना, जल संरक्षण को ईष्टतमीकरण और पुन:चक्रण करना, ठोस अपशिष्ट सामग्रियों को एकत्रित करना और पुन:चक्रित करना सहित लो कार्बन सिटी (एलसीसी) विकसित करने के लिए आधारभूत कार्य का निर्माण करते हैं। महत्वपूर्ण अवसंरचना की प्रमुख विशेषताएं जो सभी नोड्स में अपनायी जाती है, निम्नलिखित है:-

क) सभी सुविधाओं को भूमिगत बनाए जाने की योजना है जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। वे परिवहन मार्ग से बाहर भी है ताकि अनुरक्षण और अन्य कार्यों के दौरान मुख्य परिवहन मार्ग प्रभावित न हो।

ख) बस स्टेशनों को पैदल चल कर पहुंचने वाली 400 मी दूरी पर बनाया जाएगा। पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर अंतिम छोर संपर्कता विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। यातायात पर प्रभाव को कम करने के लिए बस बे/ बस स्टॉप के लिए प्रावधान।

ग) अपशिष्ट जल को एसटीपी और सीईटीपी से एकत्रित और पुन:चक्रित किया जाएगा और इसे न पीने के उद्देश्य से शहर में पुन: वितरित किया जाएगा। किसी भी ओवरफ्लो से बचने और कुशलता बनाए रखने के लिए स्काडा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। स्थायी उपाय के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) को अपनाना। औद्योगिक और रिहायशी लाइनों के लिए पृथक-पृथक सीवर लाइनें।

घ) सिटी लेवल पर वर्षा जल संग्रहित कर जल संरक्षण अपनाया गया है। उदाहरण के लिए धौलेरा में 2500 मिलियन लिटर क्षमता से अधिक वाले 100 मीटर चौड़े चैनल को वर्षा जल संग्रहण, पार्कों और बगीचों की सिंचाई के साथ-साथ न पीने के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा।

ङ) ग्रीनफील्ड सिटी की संपूर्ण अवसंरचना योजना वास्तविक समय पर सूचना और इसे प्रभावी रूप से परिचालित एवं प्रबंधित करने के लिए स्काडा, सेंसरों और ऑटोमेशन के साथ तैयार की गई है। यह इंटलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ई-गवर्नेंस, डिजीटल हेल्थ एंड एजुकेशन, इमरजेंसी और सिटी ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाएगा।

च) खुले हरित क्षेत्रों के लिए वर्गीकरण अनुक्रम द्वारा हरित क्षेत्रों की योजना जो निम्नानुसार है:

i. पांच मिनट पैदल की दूरी पर नज़दीकी पार्क;
ii. दस मिनट की पैदल दूरी पर सामुदायिक पार्क
iii. शहर के भीतर स्टोर्म वाटर केनाल के साथ लाइनर पार्क।

छ) सार्वजनिक परिवहन माध्यमों और गैर-मोटरीकृत माध्यमों से साथ एकीकृत सुरक्षित और स्थायी मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।

ज) सामाजिक अवसंरचना के साथ क्लस्टर में पार्किंग सुविधाओं वाली प्रमुख ट्रांजिट इंटरचेंजों पर नियोजित इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन।

झ) सभी झीलों को बेहतर बनाया जा रहा है और पानी की धारणीयता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नहरों की योजना है और रहने वालों के लिए मनोरंजन क्षेत्र उपलब्ध कराना।

ञ) घूमने और प्रदूषण घटाने के लिए चौड़े साइडवाक और साइकिल ट्रैक।

ट) सभी प्लॉटों और परिसंपत्तियों को देखने के लिए व्यापक वेब आधारित जीआईएस ऐप्लिकेशन। सूचना प्राप्त करने, भूमि के लिए आवेदन और आबंटन के लिए अपने आवेदन को देखने के लिए निवेशकों हेतु व्यापक ऑनलाइन भूमि प्रबंधन प्रणाली।

व्यापार और परिचालन की समग्र समीक्षा

परियोजनाओं की प्रगति की मुख्य विशेषताएं एक नजर में निम्नानुसार है:

1. डीएमआईसी प्रोजेक्ट के मामले में, निम्न चार स्थानों पर महत्वपूर्ण अवसंरचना की निर्माण संबंधी गतिविधियां जोरों पर है:

    - गुजरात में 22.5 वर्ग किमी माप का धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए सक्रियण क्षेत्र;
    - महाराष्ट्र में 18.55 वर्ग किमी क्षेत्र वाला शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का चरण-1;
    - ग्रेटर नौएडा, उत्तर प्रदेश में 747.5 एकड़ क्षेत्र वाला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट;
    - उज्जैन, मध्य प्रदेश में लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट

2. भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में 2 प्लॉट, उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप में 4 प्लॉट, मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप विक्रमउद्योगपुरी में 1 प्लॉट और महाराष्ट्र में शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में 56 प्लॉट आबंटित किए गए हैं;

3. आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम नोड और कर्नाटक में तुमकुरू नोड के लिए शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और प्रोजेक्ट एसपीवी को भी निगमित किया गया है:

4. उपरोक्त उल्लेखित परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्न परियोजनाओं के लिए भी परियोजना विकासात्मक गतिविधियां भी की जा रही है:

- हरियाणा में गुड़गांव से बावल तक और गुजरात में अहमदाबाद से धोलेरा तक मास रैपिड ट्रांजित सिस्टम (एमआरटीएस) प्रोजेक्ट;
- हरियाणा में नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच) प्रोजेक्ट;
- हरियाणा में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट;
- दादरी, उत्तर प्रदेश में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच);
- गुजरात के सानंद में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क;
- गुजरात के धौलेरा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट;
- राजस्थान में एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट।

डीएमआईसी प्रोजेक्टों की राज्य-वार प्रगति निम्नानुसार है:

गुजरात

धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर):

- विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- सभी डाऊनस्ट्रीम गतिविधियों को समन्वित कर प्रोग्राम मैनेजर कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां कर रही है;
- "धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड" नामक एसपीवी निगमित किया गया है। राज्य सरकार ने एसपीवी को 2245.08 हेक्टेयर भूमि अंतरित की है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) [पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट)] द्वारा 1294.23 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस प्रदान की है;
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने पांच पैकेजों में बंटे 2784.82 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:-

- सड़क और सेवा अनुबंध (1734 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 74.67%;
- बीईसी बिल्डिंग अनुबंध (72.31 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। क्यूब कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड चुना गया बोलीदाता है और कार्य पूरा हो गया है;
- जल शोधन संयंत्र अनुबंध (90 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एसपीएमएल चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति – 65.00%;
- मलजल उपचार संयंत्र अनुबंध (54 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति – 47.66%;
- सेंट्रल एफ्फलुएंट ट्रीटमैंट प्लांट (160 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है; जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति – 24.11%;

- आईसीटी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है और मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में टाटा केमिकल्स (126 एकड़) को 152.71 माप वाले 03 प्लॉट आबंटित किए गए हैं।
- जागरूकता जगाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो और राऊंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

<u>सानंद, गुजरात में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) (500 एकड़):</u>

- परियोजना परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- प्रस्तावित परियोजना के लिए संपर्कता योजना तैयार कर ली गई है और इसे समीक्षा तथा अनुमोदन हेतु राज्य सरकार, डीएफसीसीआईएल और रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है;
- भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है;

- राज्य सरकार ने एसपीवी निर्माण के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर सहमति दे दी है और इसे विचारार्थ एनआईसीडीआईटी को प्रस्तुत किया गया है।

<u>अहमदाबाद और धौलेरा, गुजरात के बीच एमआरटीएस:</u>

- एमआरटीएस के लिए डीपीआर तैयार हो गई है और राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दी है;
- परियोजना को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जीका रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है;
- एमआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के आरओडब्ल्यू के भाग के रूप में शुरू किया जाएगा। एनएचएआई के नियुक्त परामर्शदाता द्वारा अहमदाबाद और धौलेरा के बीच एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।
- एनएचएआई ने संपूर्ण स्ट्रेच हेतु एक्सप्रेसवे के लिए चार पैकेजों में निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है।

<u>धोलेरा, गुजरात में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट:</u>

- ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में नियुक्त मैसर्स पीडब्ल्यूसी के कॉन्सॉर्टियम को नियुक्त किया गया है;
- धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नागरिक उड्यन मंत्रालय ने परियोजना के लिए " सिद्धांतिक" स्वीकृति दे दी है;
- गुजरात राज्य सरकार ने 30 वर्ष, जिसे बाद में आपसी सहमति से आगे 30 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए प्रति वर्ष 1 रुपए की लीज किराए पर 1426 हेक्टयर भूमि उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है;
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के निदेशक मंडल ने डीपीआर और परियोजना में 51 प्रतिशत इक्विटी को अनुमोदन दे दिया है;
- एएआई, गुजरात राज्य सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच दिनांक 25.03.2019 को शेयरहोल्डर एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया;
- एनआईसीडीआईटी ने अपनी इक्विटी (16 प्रतिशत) के रूप में 19.85 करोड़ रुपए जारी किए है

भीमनाथ धोलेरा रेल लाइन प्रोजेक्ट, गुजरात:

- दिनांक 06 सितंबर, 2017 को आयोजित बैठक के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा अंतिम रुप दिए गए अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत को एसपीवी-डीआईसीडीएल निदेशक मंडल ने अनुमोदन दे दिया है।
- परियोजना को रेल मंत्रालय के गैर-सरकारी रेलवे (एनजीआर) मॉडल के लिए डीआईसीडीएल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रोजेक्ट को एनआईसीडीआईटी और गुजरात सरकार के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा और परियोजना की लागत 100 प्रतिशत इक्विटी के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा;
- परामर्शदाता द्वारा ड्राफ्ट डीपीआर को प्रस्तुत किया गया है। डीएसआईआर परियोजना के क्षेत्र के बाहर भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया गया है। डीएसआईआरडीए द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है।

महाराष्ट्र

शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए):

- एसबीआईए (8.39 वर्ग किमी) के चरण-1 के प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- सभी डाऊनस्ट्रीम गतिविधियों को समन्वित कर प्रोग्राम मैनेजर कार्यान्वयन संबंधित गतिविधियों को कर रहे हैं;
- "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड" (एआईटीएल) नामक नोड /सिटी लेवल एसपीवी निगमित किया गया है। राज्य सरकार ने एसपीवी को 8.39 वर्ग किमी भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट)) द्वारा 602.80 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;
- शेन्द्रा-बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी है;
- शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1533 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित कर दिया है। विभिन्न पैकेजों में से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:-

- सड़क, नालियों, पुलियों, जल आपूर्ति, मलजल एवं उर्जा प्रणाली के लिए ईपीसी दे दिया गया है (656.89 करोड़ रुपए)। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 87.54%;
- ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए ईपीसी (69.45 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पाटिल कन्सट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 78.62%;
- जिला प्रशासन भवन के लिए ईपीसी (129 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। कार्य पूरा हो गया है और भवन प्रयोग में है;
- मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य एफ्फुलेएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ईपीसी (72.52 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पस्सवंट एनर्जी चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 34.07%;
- लैंडस्केपिंग और जल सिंचाई कार्यों के लिए ईपीसी (112 करोड़ रुपए) दे दिया गया है, शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 20.00%;
- इंर्फोमेशन एंड कॉम्न्यूनिकेशन टेक्नोलोजी (आईसीटी) मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्यों हेतु ईपीसी (142 करोड़ रुपए) दे दिया गया है, हनीवेल चुना गया एजेंसी है। जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 72.45%;

- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों सहित 56 प्लॉट आबंटित किए गए हैं। शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एिरया में प्रथम प्रमुख निवेशक ह्योसंग कॉर्पोरेशन है (भूमि आबंटित -100 एकड़);
- बिडकिन के लिए परियोजना विकासात्मक गतिविधियां शुरू की जा रही है और 6414.21 करोड़ रुपए कीमत वाले महत्वपूर्ण अवसंरचना पैकेजों को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) [पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट) और बाद में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है;
    - राज्य सरकार ने बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रोजेक्ट एसपीवी को 1376.81 हेक्टेयर भूमि अंतरित की है और 1149.90 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी हो गई है;

- एलएंडटी को चरण-I अर्थात 10.16 वर्ग किमी में सड़क, भूमिगत सुविधाओं के लिए ईपीसी ठेकेदार (1223 करोड़ रुपए) नियुक्त किया गया है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है। जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 87.10%
- आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्य (142 करोड़ रुपए) के लिए केईसी को नियुक्त किया गया है। जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 9.00%.

दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र:

- राज्य सरकार ने चरण-1 अर्थात 3000 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली है।
- मैसर्स एजिस को विस्तृत मास्टर प्लालिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां करने के लिए नियुक्त किया गया है।

मध्य प्रदेश

पीथमपुर धार महो इन्वेस्टमेंट रीजन:

नोड/सिटी लेवल के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और मध्य प्रदेश राज्य सरकार/ एमपीटीआरआईएफएसी के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) और शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) निष्पादित किया गया है।

इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट उज्जैन:

- प्रोजेक्ट एसपीवी को 1100 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा 55.93 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- प्रोजेक्ट की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्मदा वैली डेवलपमेंट ऑथोरिटी और विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के बीच उज्जियनी से इंडस्ट्रियल एरिया विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन तक पाइप से जल आपूर्ति के लिए करार किया गया है।
- एईकॉम, प्रोग्राम मैनेजमेंट कन्सलटेंट निर्माण संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर रहा है;

- एसपीएमएल और ओम मेटल्स का कन्सॉर्टियम, ईपीसी कांट्रेक्टर, विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना घटकों का कार्यान्वयन कर रहा है। जुलाई, 2019 तक भौतिक प्रगति - 93.00%;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और अमूल को 12 एकड़ माप वाला एक प्लाट आबंटित किया गया है। कुल प्रतिबद्ध निवेश 200 करोड़ रुपए है;
- जागरूकता निर्माण और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो और राऊंड टेबल सम्मलेन को आयोजित किया गया है।

पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जल आपूर्ति योजना:

- राज्य सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के बीच डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (डीएमआईसी पीजेपीसीएल) नामक एसपीवी निगमित किया गया है;
- 306.55 करोड़ रुपए की परियोजना लागत अनुमोदित की गई है और ट्रस्ट द्वारा 17.15 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है।
- 219 करोड़ रुपए के कार्य हेतु ईपीसी कांट्रेक्टर के रूप में एलएंडटी को चुना गया है और कार्य पूरा हो गया है।
- डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड में एनआईसीडीआईटी की 49% इक्विटी शेयर होल्डिंग अधिगृहीत करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी ने अनुमोदन दे दिया है।

हरियाणा

नांगल चौधरी में इंटिग्रेटिड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच):

- प्रोजेक्ट के लिए महेंद्रगढ़ जिला में लगभग 886 एकड़ भूमि को चिह्नित किया गया है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा राज्य सरकार के बीच प्रोजेक्ट एसपीवी को निगमित किया गया है;
- राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट के लिए मास्टर प्लान योजना को अनुमोदन दे दिया है;

- सीसीईए ने चरण I विकसित करने के लिए 1029.49 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति और परियोजना के चरण II विकसित किए जाने की "सैद्धांतिक सहमति" के साथ प्रोजेक्ट को अनुमोदित कर दिया है;
- राज्य सरकार ने कुल भूमि में से 639 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 191.67 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है;
- राज्य पर्यावरण मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु प्रोजेक्ट को स्टेट एनवॉयरनमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी (एसईआईएए) को भेजने की अनुशंसा की है।
- राज्य सरकार शेष बची हुई भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्य कर रही है।
- परियोजना को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड से एनआईसीडीआईटी को ऋण वित्तपोषण के लिए रखा गया है ।

<u>मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) प्रोजेक्ट:</u>

- राज्य सरकार ने अंतिम डीपीआर को अनुमोदित कर दिया है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा सरकार के बीच प्रोजेक्ट एसपीवी निगमित किया गया है;
- भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है;
- प्रोजेक्ट को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जीका स्पेशल रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है।

<u>उत्तर प्रदेश</u>

<u>ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट:</u>

- प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूरी हो गई है और "इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड" नामक एसपीवी को निगमित किया गया है;
- प्रोजेक्ट एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा भी 617.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई;

- शपूरजी पल्लोंजी को 426 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रमुख अवसरंचना घटकों को कार्यान्वित करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है। जुलाई, 2019 तक कार्य की भौतिक प्रगति – 97.00%
- जनवरी, 2018 में सीमंस को साइट के भीतर 121 करोड़ रुपए के उर्जा वितरण कार्य करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है। जुलाई, 2019 तक कार्य की भौतिक प्रगति - 72.00%;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में हायर (123.4 एकड़) सहित चार आवेदकों को 152 एकड़ भूमि आबंटित की गई है;
- रोड शो और राऊंड टेबल कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी।

<u>दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और ग्रेटर नोएडा के बोरकी में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच):</u>

- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट के लिए एसपीवी एमएमएलएच के साथ-साथ एमएमटीएच प्रोजेक्टों को भी कार्यान्वित करेगा;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है;
- डीएफसीसीआईएल के साथ भी चर्चा शुरू हो गई है ताकि साइट को पश्चिमी और पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारे से संपर्कता उपलब्ध हो सके;
- भारतीय रेल द्वारा समझौता ज्ञापन को अनुमोदित कर दिया गया है और शीघ्र ही निष्पादित किया जाएगा;
- एनआईसीडीआईटी द्वारा अपनी पिछली बैठक में प्रोजेक्ट पर विचार किया गया था और इसे भूमि सहित 4034 करोड़ की लागत पर 80 प्रतिशत भूमि उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित किया गया था;
- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 80 प्रतिशत भूमि उनके कब्जे में है और तदनुसार प्रोजेक्ट प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी की सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया गया है;
- परियोजना को एशियन इंफ्रास्टक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एआईआईबी) से एनआईसीडीआईटी को ऋण वित्तपोषण के लिए रखा गया है।

राजस्थान

खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, राजस्थान:

- मास्टर प्लान को अधिसूचित किया गया है;
- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है;
- एसएचए एवं एसएसए के निष्पादन को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट अधिसूचित किया गया है;

राजस्थान में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट:

- नागर विमानन मंत्रालय द्वारा साइट क्लीयरेंस दे दी गई है;
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है।
- प्रस्तावित भिवाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिला अलवर, राजस्थान के लिए ईआईए स्टडी करने के लिए विचारार्थ विषयों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2017 के पत्र द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12 सितंबर, 2018 को जन सुनवाई की थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 17.01.2019 को अपनी बैठक आयोजित की और प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस देने के लिए आवेदन की समीक्षा की;
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी अंतिम डीपीआर प्रस्तुत की और राज्य सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।

जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए):

- मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिया गया है;
- राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण तेज करने के लिए अनुरोध किया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए) प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी है।

स्मार्ट कम्यूनिटी प्रोजेक्ट:

क) मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, नीमराणा, राजस्थान:

- 03 सितंबर, 2015 को 05 मैगावाट सोलर पॉवर प्लांट शुरू किया गया है। एनवीवीएन लिमिटेड के साथ पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के अनुसार 8.77/- रुपए प्रति यूनिट के निर्धारित टैरिफ पर स्टेट ग्रिड (अर्थात 220 केवी जीएसएस नीमराणा) को भेजी जा रही है।
- 17 मई, 2016 से 10 वर्षों के लिए 11.99/- रुपए प्रति यूनिट के निश्चित टैरिफ के आधार पर एमआईकेयूएनआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 01 मैगावाट माइक्रो ग्रिड सोलर पॉवर प्लांट के लिए पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) निष्पादित किया गया है।
- 10 जुलाई, 2017 से एमआईकेयूएनआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उच्च गुणवत्ता, स्थिर और नवीकरणीय योग्य हरित उर्जा भेजने के लिए 01 मैगावाट माइक्रो ग्रिड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट से उर्जा उत्पादन शुरू हो गया है।

ख) लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट:

- 01 जुलाई, 2016 से जेएनपीटी पोर्ट पर परिचालन और 01 अप्रैल, 2018 से जेएनपीटी पोर्ट पर भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल नामक नया पोर्ट टर्मिनल की शुरूआत;
- 01 मई, 2017 से गुजरात में एपीएसईजेड मुंद्रा (अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनोमिक जोन) एवं एएचपीपीएल हजीरा (अडानी हजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड) पर सभी कंटेनर टर्मिनलों ने सफलतापूर्वक परिचालन शुरू कर दिया है;
- 20 अगस्त, 2019 तक 18 मिलियन से अधिक कंटेनरों को टैग्गड/डी-टैग्गड किया गया है;
- पूरे भारत में एलडीबी सेवाओं के विस्तार हेतु तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णपट्नम पोर्ट, एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, हल्दिया, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं।

अन्य परियोजनाएं:

द्वारका, दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी):

- मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है और परियोजना के मार्गदर्शन हेतु प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है;
- परियोजना के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के नाम से एसपीवी बनाया गया है।
- डीआईपीपी द्वारा डीडीए से भूमि लेना शुरू हो गया है;
- विभिन्न परियोजना विकास गतिविधियों को करने के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट कन्सलटेंट के रूप में एईसीओएम को नियुक्त किया गया है;
- चरण 1 घटकों (2791 करोड़ रुपए) के विकास के लिए एलएंडटी को ईपीसी कांट्रेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, जुलाई, 2019 तक कार्य की भौतिक प्रगति – 53.60%;
- डीएमआरसी ने 18 जुलाई, 2018 को भूमि मालिकों को बकाये का भुगतान कर शेष 0.1368 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई), आदि जैसे भागीदारों के परामर्श से अन्य परियोजना संबंधी विकासात्मक गतिविधियां की जा रही है;
- एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के आईआईसीसी प्रोजेक्ट तक विस्तार हेतु डीएमआरसी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है और निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है;
- एएआई ने परियोजना के लिए प्रस्तावित भवन ऊंचाइयों पर "अनापत्ति प्रमाणपत्र" दे दिया है;
- दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने इमारत के नक्शे को अनुमोदन दे दिया है और दिल्ली फायर सर्विसेस ने चरण-1 विकास के लिए इमारत के नक्शे को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है।
- एचवीपीएनएल एवं बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड ने एचटी लाइनें जो साइट से गुजर रही थी, उन्हें हटाने का कार्य पूरा कर लिया है;
- परियोजना की प्रगति पर निगरानी के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठक की जा रही है;

- बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप को व्यवसायीकरण, नियोजन एवं कर्षण परामर्शदाता के रूप में और आईडीओएम (स्पेन) एवं सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स के कॉन्सोर्टियम को प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर संबंधी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- कोरिया इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर एंड ईसेंग नेटवर्क कंपनी लिमिटेड के कॉन्सोर्टियम को एक्जीबिशन एवं कन्वेन्शन सेंटर के लिए परिचालक के रूप में नियुक्त किया गया है और परिचालन सेवा अनुबंध 20 वर्ष की अवधि का है;
- आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड को ऋण जुटाने के लिए वित्तीय परामर्शदाता के रूप नियुक्त किया गया है;
- शिलान्यास समारोह 20 सितंबर, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
- नेशनल कौंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स को "थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑडिट" (टीपीक्यूए) के लिए परामर्शदाता सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है;
- आईआईसीसी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से एसबीआई के साथ 2150.16 करोड़ रुपए के आवधिक ऋण को अंतिम रूप दिया गया है।
- आईआईसीसी द्वारका की थोक बिजली आपूर्ति के लिए दिनांक 14 जनवरी, 2019 को बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीपीआरएल) एवं आईआईसीसी के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।

<u>अन्य औद्योगिक गलियारे:</u>

क. चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी) प्रोजेक्ट:

- सभी गलियारों के लिए भावी योजना पूरी हो गई है और विकास के लिए तीन नोड्स की पहचान की गई है;
  i. कृष्णपट्नम, आंध्र प्रदेश;
  ii. तुमकुरू, कर्नाटक; और
  iii. पोन्नेरी, तमिलनाडु।

i. कृष्णपट्नम, आंध्र प्रदेश:

- शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किया गया है और 07 अगस्त, 2018 को 'एनआईसीडीआईटी कृष्णपटनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलेपमेंट लिमिटेड" नामक प्रोजेक्ट एसपीवी निगमित किया गया है।

- सक्रियण क्षेत्र (2500 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और परियोजना प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।
- पर्यावरण प्रभाव आंकलन के लिए परामर्शदाता सेवाएं हेतु एलएंडटी को लैटर ऑफ एवार्ड जारी कर दिया गया है;

ii. तुमकुरू, कर्नाटक:

- शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किया गया है और 01 नवंबर, 2018 को प्रोजेक्ट एसपीवी अर्थात सीबीआईसी तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड निगमित किया गया है।
- सक्रियण क्षेत्र (1736 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और परियोजना प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

iii. पोन्नेरी, तमिलनाडु:

- तमिलनाडु में पोन्नेरी नोड के लिए राज्य सरकार ने शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को सहमति दे दी है। इसे एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

ख. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एकेआईसी) प्रोजेक्ट:

- सभी गलियारों के लिए भावी योजना तैयार कर ली गई है और चरण-I के अंतर्गत विकास के लिए सात औद्योगिक विनिर्माण कलस्टरों (आईएमसी) की पहचान की गई है। ये आईएमसी राजपुरा-पटियाला (पंजाब), गोहाना (हरियाणा), प्राग-खुरपिया फार्म (उत्तराखंड), भाऊपुर (उत्तर प्रदेश), गमहरिया (बिहार), बरही (झारखंड) और रघुनाथपुर (पश्चिम बंगाल) है;
- सभी पहचाने गए आईएमसी के लिए कॉन्सेप्ट मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है;
- राजपुरा-पटियाला (पंजाब), गोहाना (हरियाणा), प्राग-खुरपिया फार्म्स (उत्तराखंड), भाऊपुर (उत्तर प्रदेश), गमहरिया (बिहार), बरही (झारखंड) आईएमसी के लिए संबंधित राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।

i. **रघुनाथपुर, पश्चिम बंगाल**

- राज्य सरकार के साथ शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- 2483 एकड़ भूमि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कब्जे में है
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां प्रगति पर है;

डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट शहरों के लिए पुरस्कार और सम्मान

धौलेरा स्मार्ट सिटी:

1. जियोस्पेटियल एक्सीलेंस एवार्ड, मार्च, 2016
2. बेंटले "बी इन्सपायर्ड", मार्च, 2016
3. आईजीबीसी ग्रीन सिटी रेटिंग "प्लेटिनम", सितंबर, 2016
4. बेस्ट सिटी फॉर इंटीग्रेटिड प्लानिंग, फरवरी, 2017
5. बेस्ट ग्रीन सिटी, फरवरी, 2017
6. बेस्ट इनोवेटिव ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट, फरवरी, 2019

औरिक स्मार्ट सिटी:

1. औरिक हॉल - सर्वश्रेष्ठ भवन और सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर के लिए 2017 टाइम्स नेशनल एवार्ड
2. 2018 नेशनल सेफ्टी कौंसिल अवसंरचना प्रोजेक्ट के लिए दूसरा स्थान 3.2 मिलियन सेफ मेनऑवर
3. ई-लैंड मैनेजमेंट प्रणाली के लिए 2018 स्कॉच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट एवार्ड
4. सैन फ्रांसिसको में टेक्नोलोजी मेरिट : स्मार्ट सिटी के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए 11 ईबीजे/सीसीबीजे एवार्ड

- **टेक्नोलोजी मेरिट: स्मार्ट सिटी:** औरिक (औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी) को भविष्य की एक स्मार्ट, हरित औद्योगिक शहर में बदलने के लिए विस्तारित औरंगाबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, एकीकृत स्मार्ट प्रौद्योगिकियां और अगली पीढ़ी की अवसंरचना

वित्तीय परिणाम सार

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, ट्रस्ट के मेन कार्प्स और एडिशनल कार्प्स के लिए भारत सरकार द्वारा क्रमश: 998.52 करोड़ रुपए और 98.48 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रस्ट का वित्तीय सार निम्नानुसार है:

(रु करोड़ों मे)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19 (लेखा परीक्षित)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (लेखा परीक्षित)
कार्प्स/पूंजी निधि*	4740.06	3727.00
स्थायी परिसंपत्तियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवेश	4421.60	3473.62
चालू परिसंपत्तियां	318.51	253.51
चिन्हित निधि*	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चालू दायित्वाएं	0.06	0.13
गैर-चालू दायित्वाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सकल आय	28.88	13.53
व्यय पर आय का आधिक्य/(कमी)	17.06	(1.59)

लेखा परीक्षक

ट्रस्ट डीड के परिच्छेद 13 के अनुसार, एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन है।

भारत के राष्ट्रपति ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सीएंडएजी को एनआईसीडीआईटी की लेखा परीक्षा का कार्यभार सौंपा है।

वर्ष के दौरान, सीएंडएजी लेखा परीक्षा टीम ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा और ट्रांसक्शन ऑडिट की है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एनआईसीडीआईटी के स्वीकृत वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा सीएंडएजी द्वारा हो गयी है।

कर्मचारियों के ब्यौरे

वर्ष 2018-19 के दौरान एनआईसीडीआईटी में कोई कर्मचारी नहीं है।

ट्रस्ट डीड के परिच्छेट 8.5 के अनुसार, सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, डीएमआईसीडीसी लिमिटेड एनआईसीडीआईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

आभार

ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ट्रस्टियों को ट्रस्ट में उनके निरंतर समर्थन, सहयोग और योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट
एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 19 अगस्त, 2020

संख्या / No.

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated

सेवा में ,

सचिव,भारत सरकार ,
वाणिज्य एवं उधोग मत्रालय,
उधोग भवन,
नई दिल्ली

विषय- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखाओ पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट के वर्ष 2018-19 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

हस्ता0
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

संख्या:- PDCA|ND|CHQ-D|27-17|19-20|928 दिनाँक:- 13 3.2020

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट अध्यक्ष, कमरा संख्या-341 तीसरी मंजिल, होटल अशोक, नई दिल्ली-110021 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

प्राची 13.3.20
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) जिसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग (बजट प्रभाग) के दिनांक 1 सितंबर, 2014 के सुपुर्दगी पत्र सं. 1(27)-बी(आर)/2013 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलेपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण ट्रस्ट के दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटन शर्तों, आदि के साथ अनुरूपता के संबध में केवल लेखांकन उपचारों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की विवेचना शामिल है। वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण कानूनों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में है और कुशलता-सह-प्रदर्शन पहलूओं, आदि, यदि कोई हो तो इसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा में पृथक रिपोर्ट से दिखाया गया है।

3 हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा की जाती है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का नियोजन तथा प्रदर्शन इस तरह करे कि ये वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण चूक से मुक्त हो। किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थ करने वाले साक्ष्यों को जांच आधार पर परीक्षण करना है। किसी लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन मानकों और प्रबंधन द्वारा तैयार महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के आंकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे विचारों के लिए उचित आधार मुहैया कराती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास से हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में बनाए गए हैं।

(iii) हमारे विचार में, लेखा बहियों की हमारी जांच से अभी तक यह प्रतीत होता है कि दिनांक 27 सितंबर, 2012 की न्यास विलेख की उपधारा 13.1 के अंतर्गत जैसा अपेक्षा की गई है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट द्वारा लेखा बहियों और अन्य संबंधित रिकार्डों को उचित रूप से तरीके से बनाए रखा है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

सहायता अनुदान

परियोजना कार्यान्वयन निधि और परियोजना विकास निधि के अंतर्गत सहायता अनुदान की स्थिति (प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार) निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**परियोजना कार्यान्वयन निधि (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए)**	**परियोजना विकास निधि (परियोजना विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए)**
अथशेष	28.36	0.02
जोड़े: 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुदान	998.52	98.48
जोड़े: 2018-19 के दौरान प्राप्त ब्याज	13.68	0.50
जोड़े: डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान	1.10	-
जोड़े: डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डाटा सर्विस लिमिटेड द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान	6.00	-
जोड़े: आयकर रिफंड	6.36	2.04
जोड़े: प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त राशि	57.21	-
कुल उपलब्ध धनराशि	**1111.23**	**101.04**
घटाए:- उपयोग की गई धनराशि	1009.87	101.00
31.03.2018 को इतिशेष	101.36	0.04

(v) हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारे विचार और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उल्लेखित वित्तीय विवरण जिसे लेखांकन नीतियों और लेखों पर नोट के साथ पढ़ा जाए,

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और उचित विचार प्रकट करते हैं;

a) अभी तक यह 31 मार्च, 2019 को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलेपमैंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के तुलन-पत्र से संबंधित है और

b) अभी तक यह उसी तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए आय की अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते

नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 13 मार्च, 2020

(प्राची पाण्डेय)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I

नई दिल्ली

अनुलग्नक

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलेपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट हेतु)

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली**

   वर्ष 2018-19 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टड एकाऊंटेंसी फर्म द्वारा की गई थी।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

   आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुसार है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

   ट्रस्ट के पास कोई स्थायी परिसंपत्ति नहीं है।

4. **वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

   ट्रस्ट के पास कोई वस्तुसूची नहीं है।

5. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता**

   सामान्य रूप से ट्रस्ट नियमित रूप से सांविधिक बकायों का भुगतान करती है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र
31 मार्च, 2019 को

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2018-19	2017-18
कार्प्स / पूंजी निधि और देयताएं			
कार्प्स/पूंजी निधि	1	47,40,05,82,863	37,26,99,54,627
आरक्षित और अधिशेष	-	-	-
चिन्हित/ बंदोबस्त निधि	-	-	-
ऋण और उधार	-	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	2	5,72,110	12,67,341
जोड़		**47,40,11,54,973**	**37,27,12,21,968**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-
निवेश	3	44,21,60,25,101	34,73,61,72,881
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	3,18,51,29,872	2,53,50,49,087
जोड़		**47,40,11,54,973**	**37,27,12,21,968**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लेखित अनुसूचियां इस तुलन पत्र का भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

(अल्केश कुमार शर्मा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

(गुरूप्रसाद मोहपात्रा)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30 अगस्त, 2019

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय और व्यय लेखा
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2018-19	2017-18
आय			
अर्जित ब्याज	5	26,59,97,977	13,23,35,360
अन्य आय	6	2,27,55,993	29,79,496
जोड़ (क)		**28,87,53,970**	**13,53,14,856**
व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय	7	11,81,25,734	15,12,06,393
जोड़ (ख)		**11,81,25,734**	**15,12,06,393**
आय का व्यय पर आधिक्य के बाद शेष (क-ख)		17,06,28,236	-1,58,91,537
अतिरिक्त कार्प्स को अंतरित		51,20,754	1,50,80,947
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरित		-	-
अधिशेष/(कमी) होने के कारण मुख्य कार्प्स/ पूंजी निधि में अग्रेषित		**16,55,07,482**	**(3,09,72,484)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लेखित अनुसूचियां इस तुलन पत्र का भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

(अल्केश कुमार शर्मा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

(गुरूप्रसाद मोहपात्रा)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30 अगस्त, 2019

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

प्राप्ति और भुगतान
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

प्राप्ति	2018-19	2017-18	भुगतान	2018-19	2017-18
I. **अथशेष**			I. **व्यय**		
क) रोकड़ शेष	-	-	अन्य प्रशासनिक व्यय	11,88,20,965	15,02,92,802
ख) बैंक शेष					
i) बचत खाते में	97,29,855	16,48,662	II. **विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए किया गया भुगतान**		
ii) जमा खातों में	27,41,20,456	6,70,70,29,237	क) मुख्य निधि से		
			निम्न को जारी ऋण:		
			i) डीएमआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर कंपनी लिमिटेड	-	3,60,00,000
II. **प्राप्त अनुदान**			ii) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	50,00,00,000	1,32,54,00,000
क) मुख्य निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त	9,98,51,74,213	8,01,37,00,000	ख) अतिरिक्त निधि में से		
ख) अतिरिक्त निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त	98,48,25,787	-	- डीएमआईसीडीसी लिमिटेड को जारी सहायता अनुदान	1,01,00,00,000	87,55,27,000
III. **निम्न के निवेशों पर आय**					
क) मुख्य निधि	45,33,641	-	III. **निम्न में से किया गया निवेश और जमाएं**		
ख) अतिरिक्त निधि	-	-	क) मुख्य निधि में से	9,47,98,52,220	11,65,01,74,881
IV. **प्राप्त ब्याज**					
क) बैंक जमाओं पर (टीडीएस के बाद)	10,56,92,135	2,63,82,982	IV. **स्थायी परिसंपत्तियों एवं चालू पंजीगत कार्यों पर व्यय**	-	-
ख) बचत खातों पर	12,68,395	1,86,53,546			
ग) ऋण और अग्रिम (टीडीएस के बाद)	1,20,70,743	2,06,87,765			
			V. **अधिशेष धनराशि/ऋणों को लौटाना**	-	-
V. **अन्य आय**					
क) मुख्य निधि	1,38,18,374	25,15,742	VI. **वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	-	-
ख) अतिरिक्त निधि	44,03,978	4,63,754			
			VII. **अन्य भुगतान**		
VI. **उधार ली गई राशि**	-	-	एसपीवी के लिए वहन किए गए व्यय	-	-
			आईआईसीसी लिमिटेड के लिए वहन किया गया व्यय	-	57,20,82,739
VII. **अन्य कोई प्राप्तियां**					
निम्न द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान:					
(i) डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड	1,10,00,000	6,64,89,756	VIII. **जमा शेष**		
(ii) डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेस लिमिटेड	6,00,00,000	-	क) रोकड़ शेष	-	-
रिफंड आयकर	8,40,21,438	3,31,05,504	ख) बैंक शेष		
आईआईसीसी लिमिटेड के लिए वहन किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति	57,20,82,739	26,50,785	i) बचत खातों में	1,03,179	97,29,855
			ii) जमा खातों में	1,01,39,65,390	27,41,20,456
जोड़	**12,12,27,41,754**	**14,89,33,27,733**	**जोड़**	**12,12,27,41,754**	**14,89,33,27,733**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30 अगस्त, 2019

(अल्केश कुमार शर्मा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

(गुरूप्रसाद मोहपात्रा)
अध्यक्ष

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च, 2019 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2018-19	2017-18
अनुसूची 1: कार्प्स/पूंजी निधि			
1.0. मुख्य कार्प्स/पूंजी निधि			
वर्ष की शुरूआत में शेष		37,23,97,74,984	29,30,18,90,510
जोड़े: कार्प्स/पूंजी निधि के लिए प्राप्त अंशदान		9,98,51,74,213	8,01,37,00,000
जोड़े/(घटाएं): जैसा अब पीआईएफ में सुधार किए गए के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में लेखाबद्ध पीडीएफ संबंधित ब्याज		-	(11,43,042)
जोड़े/(घटाएं): आय एवं व्यय लेखों से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष		16,55,07,482	(3,09,72,484)
जोड़े/(घटाएं): अतिरिक्त कार्प्स को अंतरित राशि*		-	(4,37,00,000)
वर्ष के अंत में शेष (क)		**47,39,04,56,679**	**37,23,97,74,984**
1.1. डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के लिए अतिरिक्त कार्प्स			
वर्ष की शुरूआत में शेष		2,29,26,00,000	2,24,89,00,000
जोड़ें: अतिरिक्त कार्प्स/पूंजी निधि के लिए अंशदान		98,48,25,787	-
जोड़े: मुख्य कार्प्स से अंतरित राशि*		-	4,37,00,000
	(अ)	3,27,74,25,787	2,29,26,00,000
जोड़े: आय और व्यय लेखा से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष			
- पिछले वर्षों के दौरान		37,63,06,643	36,00,82,654
जोड़े/ (घटाएं): जैसा अब पीआईएफ में सुधार किए गए के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में लेखाबद्ध पीडीएफ संबंधित ब्याज		-	11,43,042
- चालू वर्ष के दौरान		51,20,754	1,50,80,947
	(आ)	38,14,27,397	37,63,06,643
	(अ) + (आ)	**3,65,88,53,184**	**2,66,89,06,643**
घटाएं: डीएमआईसीडीसी लिमिटेड को अनुदान जारी कर उपयोग की गई राशि			
- पिछले वर्षों के दौरान		2,63,87,27,000	1,76,32,00,000
- चालू वर्ष के दौरान		1,01,00,00,000	87,55,27,000
	(इ)	3,64,87,27,000	2,63,87,27,000
वर्ष के अंत में शेष [ख = (अ) + (आ) - (इ)]		**1,01,26,184**	**3,01,79,643**
सकल जोड़ (क+ख)		**47,40,05,82,863**	**37,26,99,54,627**

* द्वारका, नई दिल्ली में एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट की परियोजना-पूर्व गतिविधियां करने के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन (डीएमआईसीडीसी) लिमिटेड को इन निधियों को अंतरित करने हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु गैर-आवर्ती अनुदान के प्रति उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से प्राप्त राशि। तदनुसार, द्वारका, नई दिल्ली में एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट के परियोजना-पूर्व व्यय के लिए निधियां डीएमआईसीडीसी लिमिटेड को अंतरित की गई थी।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च, 2019 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2018-19	2017-18
अनुसूची 2 : चालू देयताएं और प्रावधान			
2.0. चालू देयताएं			
1. विविध लेनदार:			
(क) माल के लिए		-	-
(ख) अन्य		1,28,610	9,47,341
2. सांविधिक देयताएं			
(क) अन्य			
- स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)		8,500	5,000
	(क)	1,37,110	9,52,341
2.1. प्रावधान			
1. अन्य			
(क) लेखा परीक्षा फीस के लिए प्रावधान			
- चालू वर्ष		1,70,000	1,50,000
- पिछले वर्ष		2,65,000	1,65,000
	(ख)	4,35,000	3,15,000
जोड़ (क + ख)		**5,72,110**	**12,67,341**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च, 2019 को

(राशि रुपए में)

विवरण	2018-19	2017-18
अनुसूची 3 : निवेश		
1. चिन्हित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश	-	-
2. निवेश - अन्य		
(क) शेयर		
- पीथमपुर जल प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	17,15,00,000	17,15,00,000
- विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	55,93,00,000	55,93,00,000
- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	6,17,20,00,000	6,17,20,00,000
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	17,52,70,00,000	14,52,70,00,000
- धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेव. लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	17,45,54,08,351	12,94,22,74,881
- डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	4,01,98,000	4,01,98,000
- डीएमआईसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	1,96,67,18,750	5,00,00,000
- धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड* के इक्विटी शेयरों में निवेश	4,39,00,000	4,39,00,000.00
- सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	2,50,00,000	-
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश	2,50,00,000	-
(ख) अन्य		
- मैसर्स डीएमआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए डीएमआईसीडीसी लिमिटेड जारी निधियां (अनुसूची-9 का संदर्भ नोट सं. 3)	13,00,00,000	13,00,00,000
जोड़	**44,21,60,25,101**	**34,73,61,72,881**

* भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की सिफारिश के अनुसार, एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 23 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के स्वातमित्व के धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड के 10/- रुपए के सम मूल्य वाले 43,90,000 शेयर नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीडीसी-पीआईटीएफ) के नाम से पहचाना जाता था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में अंतरित करने को अनुमोदन दिया।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च, 2019 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2018-19	2017-18
अनुसूची 4 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि			
4.0. चालू परिसंपत्तियां:			
1. अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष:			
(क) जमा खातों में			
- मुख्य कार्पस		1,01,36,10,390	27,39,85,456
- अतिरिक्त कार्पस		3,55,000	1,35,000
(ख) बचत खातों में			
- मुख्य कार्पस		50,818	96,89,202
- अतिरिक्त कार्पस		52,361	40,653
	(क)	**1,01,40,68,569**	**28,38,50,311**
4.1. ऋण, अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ:			
1. ऋण और अग्रिम:			
डीएमआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर कंपनी लिमिटेड को		2,50,00,000	3,60,00,000
डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेस लिमिटेड को		6,75,00,000	12,75,00,000
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड को		1,82,54,00,000	1,32,54,00,000
2. बैंकों के पास जमाओं पर अर्जित ब्याज:			
मुख्य कार्पस		45,75,903	81,66,889
अतिरिक्त कार्पस		115	2,967
3. ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज:			
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड से		17,65,09,309	5,24,80,593
4. अन्य:			
स्रोत पर काटा गया कर			
- मुख्य कार्पस		6,22,74,769	9,94,62,984
- अतिरिक्त कार्पस		98,01,207	3,00,99,869
अन्य ऋण और अग्रिम*		-	57,20,85,474
	(ख)	**2,17,10,61,303**	**2,25,11,98,776**
जोड़ (क + ख)		**3,18,51,29,872**	**2,53,50,49,087**

*शामिल:

(i) द्वारका, नई दिल्ली में एक्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट व्यय पूरे करने के लिए ये निधियां इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), जिसे पूर्व में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के नाम से पहचाना जाता था, के दिनांक 06 मार्च, 2018 के स्वीकृति आदेश सं. पी-40019/4/2017-आईडी-आई(पार्ट) द्वारा प्राप्त की गई राशि 52,20,82,739 रुपए थी और इसे 03 अप्रैल, 2018 को एनआईसीडीआईटी को आईआईसीसी लिमिटेड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है; और

(ii) आईआईसीसी लिमिटेड की प्रारंभिक चुकता पूंजी के लिए दिनांक 08.12.2017 के पत्र सं. पी-40022/67/2017-आईडी-आई द्वारा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से आईआईसीसी लिमिटेड को 5,00,00,000 की राशि अंतरित की गई थी और इसे दिनांक 11 मई, 2018 की स्वीकृति आदेश सं. पी-40019/4/2017-आईडी-आई(पार्ट) द्वारा एनआईसीडीआईटी को डीपीआईआईटी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय एवं व्यय के भाग बनने वाले नोट
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	2018-19	2017-18
अनुसूची 5 : अर्जित ब्याज		
(1.) अवधि जमाओं पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कार्प्स	11,28,82,992	2,24,36,155
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 1,12,88,345/-		
(पिछले वर्ष - ₹ 22,36,235/-)]		
(ख) अतिरिक्त कार्प्स	6,24,969	1,46,02,569
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 1,24,054/-		
(पिछले वर्ष - ₹ 14,62,881/-)]		
(2.) बचत खातों पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कार्प्स	11,76,588	1,86,38,922
(ख) अतिरिक्त कार्प्स	91,807	14,624
(3.) ऋण पर:	15,12,21,621	7,66,43,090
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 1,51,22,162/-		
(पिछले वर्ष - ₹ 76,64,310/-)]		
जोड़	**26,59,97,977**	**13,23,35,360**
अनुसूची 6: अन्य आय		
आयकर रिफंड पर ब्याज		
(क) मुख्य कार्प्स	1,38,18,374	25,15,742
(ख) अतिरिक्त कार्प्स	44,03,978	4,63,754
लाभांश आय	45,33,641	-
जोड़	**2,27,55,993**	**29,79,496**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय एवं व्यय के भाग बनने वाले नोट
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	2018-19	2017-18
अनुसूची 7 : अन्य प्रशासनिक व्यय		
सेवा फीस	11,77,62,257	15,04,58,063
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक		
- चालू वर्ष	1,70,000	1,65,000
- पिछले वर्ष	5,320	60,640
विज्ञापन व्यय	-	2,25,277
फाइलिंग फीस पर व्यय	9,743	1,11,990
पेशेवर और परामर्श फीस	94,000	68,800
बैठक और कांफ्रेंस व्यय	19,411	1,11,837
अवधि पूर्व व्यय	35,000	-
अन्य		
- विविध व्यय	30,003	4,786
जोड़	**11,81,25,734**	**15,12,06,393**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूची
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.0 लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत और जब तक उल्लेखित न हो, लेखांकन की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किया गया है।

2.0 दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेश को अभिग्रहण की प्रासंगिक लागत सहित वास्तविक लागत पर प्रदर्शित किया गया है।

3.0 स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाकर प्रदर्शित किया गया है;

3.2 जैसा प्रबंधन द्वारा अपेक्षा की गई है, अभिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार न हो;

3.3 स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित उत्तरवर्ती व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ ट्रस्ट को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। मरम्मत और अनुरक्षण लागतें जब वहन की जाती है, तो आय और व्यय लेखा में प्रदर्शित किया जाता है;

3.4 मूल्यह्रास को ह्रासित मूल्य पर मूल्यह्रासित किए जाने तक आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होता है।

4.0 सरकारी अनुदान

4.1 ट्रस्ट निम्न के लिए भारत सरकार से पृथक रूप से गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान प्राप्त करता है:

(i.) ट्रस्ट के मुख्य काप्र्स से "पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन" को "काप्र्स/पूंजी निधि" के अंतर्गत "मुख्य काप्र्स" में दर्शाया गया है; और

(ii.) परियोजना विकासात्मक गतिविधियों को करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड को दिए जाने वाले चिन्हित "सामान्य" को "काप्र्स/पूंजी निधि" के अंतर्गत "अतिरिक्त काप्र्स"" के रूप में दर्शाया गया है।

यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षणों के अनुसार किया गया है।

4.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

5.0 राजस्व स्वीकरण

5.1 आय को प्रोद्भवन आधार पर स्वीकारा जाता है।

5.2 "मुख्य कार्प्स" और "अतिरिक्त कार्प्स" की अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज को इन संबंधित शीर्षों के अंतर्गत विशेष रूप में दर्शाया जाता है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण के अनुसार है।

6.0 अन्य प्रशासनिक व्यय

अन्य प्रशासनिक व्ययों को "मुख्य कार्प्स/पूंजी निधि" के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान की अधिशेष निधि पर ब्याज आय से पूरा किया जाता है।

7.0 सेवा फीस

डीएमआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सेवा फीस को 26 जुलाई, 2016 से प्रभावी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पीआईएफ) में विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए ट्रस्ट द्वारा जारी निधियों के 1 प्रतिशत की दर से (एक वर्ष में 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन) प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया जाता है।

8.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा में व्यय/लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर विनिमय की प्रचलित बाजार दर पर लेखाबद्ध किया जाता है और विदेशी मुद्राओं में आय इन मुद्राओं से वसूली गई कीमत पर लेखाबद्ध की जाती है।

9.0 लीज

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभों को अपने पास रखता है। लीज अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिचालन लीज भुगतान को प्रोद्भवन आधार पर आय और व्यय विवरण में व्यय के रूप में स्वीकारा जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

1.0 भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार ट्रस्ट डीड के निष्पादन द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2012 को डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड) का गठन किया गया था।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने मौजूदा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के साथ अन्य इंडस्ट्रियल कोरिडोरों यथा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी), बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी), चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्टो (वीसीआईसी) शामिल करने के लिए ट्रस्ट के अधिदेश का विस्तार करने और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन:नामित करने के लिए दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को भारत सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन को दिनांक 22.12.2016 के आदेश सं. 11/1/2016 द्वारा सूचित किया।

2.0 15 सितंबर, 2011 को भारत सरकार से अनुमोदित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) में औद्योगिक शहरों के विकास के लिए वित्तीय और संस्थानिक संरचना के अनुसार, भारत सरकार औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 2011-12 में शुरू होकर अगले पांच वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान देगी। परियोजना विकासात्मक गतिविधियां करने और परियोजना विशिष्ट एसपीवी के निर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों की सीमा में प्रोजेक्ट विशिष्ट एसपीवी वाली सेक्टोरल होल्डिंग कंपनियों के निर्माण हेतु अगले पांच वर्षों में सहायता अनुदान के रूप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड को देने के लिए ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कार्प्स दिया जाएगा।

भारत सरकार ने 07 दिसंबर, 2016 को अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 तक की विस्तारित अवधि में 1584 करोड़ रुपए (अर्थात अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए 1500 करोड़ रुपए और एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय के लिए 84 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त स्वीकृति सहित उपर्युक्त अनुमोदित वित्तीय सहायता उपयोग करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है।

वर्ष के दौरान, डीएमआईसीडीसी लिमिटेड को देने हेतु मुख्य कार्प्स/पूंजी निधि में 998.52 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 801.37 करोड़ रुपए) और अतिरिक्त कार्प्स के लिए 98.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष कुछ नहीं) की राशि प्राप्त की गई थी।

भारत सरकार के योगदान को परिक्रामी कार्प्स निधि के रूप में उपयोग किया जाएगा।

3.0 आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 6.00 मैगा वाट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए डीएमआईसीडीसी द्वारा ट्रस्ट में 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश हेतु अपने 100 प्रतिशत स्वामित्व वाले "डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड" नामक एसपीवी को बाद में जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य कार्प्स/पूंजी निधि में से डीएमआईसीडीसी लिमिटेड को 13,00,00,000/- की राशि अंतरित की गई थी। इस तरह के निवेश में वृद्धि डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आ जाएगी। जारी की गई राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की कार्प्स निधि से घटा दी गई थी।
लेन-देनों के प्रकटन के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सिफारिशों पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति के मतानुसार, ट्रस्ट की मुख्य कार्प्स /पूंजी निधि से घटाई गई राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुन: जोड़ा गया था।

तदनुरूपी प्रकटन को "निवेश" शीर्ष के अंतर्गत किया गया है।

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

4.0 कर्मचारी हितलाभ

ट्रस्ट के पास कोई कर्मचारी नहीं है। रिटायरमेंट सहित कर्मचारी हितलाभ के मद में देयता का प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

5.0 आकस्मिक देयताएं

ट्रस्ट की आकस्मिक देयता शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

6.0 पूंजीगत वचनबद्धताएं

ट्रस्ट की पूंजीगत वचनबद्धताएं शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

7.0 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम व्यापार की साधारण अवधि में वसूले जा सकने योग्य मूल्यों पर है जो तुलन पत्र में उल्लिखित की गई राशि से कम नहीं होगी।

8.0 करारोपण

आयकर निदेशक (छूट) ने 28 मार्च, 2013 को ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आंकलन वर्ष 2013-14 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए जिसे धारा 12एए के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया है। तदनुसार, ट्रस्ट ने आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

	राशि (₹) 2018-19	राशि (₹) 2017-18
9.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन		
9.1 विदेशी मुद्रा में आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.2 विदेशी मुद्रा में व्यय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.0 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		
10.1 लेखा परीक्षक फीस		
- चालू वर्ष के लिए	1,70,000	1,65,000
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए	5,320	60,640
10.2 कर संबंधी मामलों के लिए	-	-
10.3 अन्य सेवाओं के लिए	-	-

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

11.0 परियोजना विकासात्मक व्यय

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रेक्षणों के अनुसार, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच संबंधित सहायक उपक्रमों/गठित एसपीवी को परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा वहन किए 'परियोजना विकास व्यय' अंतरित करने के मामले को दिनांक 06.03.2018 की एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल की बैठक में विचारार्थ रखा गया।

न्यासी मंडल के निर्देशों के अनुसार संबंधित सहायक उपक्रमों/एसपीवी को सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई परियोजना विकास निधि में से उल्लेखित सहायक उपक्रमों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में डीएमआईसीडीसी द्वारा वहन किए गए 'परियोजना विकास व्यय' संबंधित एसपीवी को अंतरित कर दिए गए हैं और एसपीवी द्वारा पर्याप्त अधिशेष निधि सृजित करने में सक्षम होने तक इसकी वसूली रोक दी गई है।

इसके अतिरिक्त, डीएमआईसीडीसी लिमिटेड की लेखांकन नीतियों के अनुसार, परियोजनाओं के लिए वहन किए गए परियोजना विकास व्यय जिन्हें शुरू नहीं किया गया है अथवा कोई गतिविधि नहीं की गई है अथवा एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य(यों)/नोडल एजेंसियों के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट इस प्रकार की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, उन्हें डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में 'पूंजी संचय' के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से कमी के रूप में प्रकट किया गया है।

12.0 प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्ति और भुगतान लेखा को वर्ष के दौरान रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर तैयार किया गया है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रेक्षणों के आधार पर है।

13.0 जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया हो, पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को पुन:समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

14.0 अनुसूची 1 से 9 जोड़े गए है और 31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के आंतरिक भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

(अल्केश कुमार शर्मा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

(गुरूप्रसाद मोहपात्रा)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अगस्त, 2019

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

ANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2018-19

Proforma for furnishing the relevant details in respact of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat

Name of the Ministry:- Ministry of Commerce and Industry
Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Name of Organization: National Industrial Corridor Development & Implementation Trust

Sr. No.	Particulars	Remark		
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Trust		
2	The Year of inception of the organisation	2012		
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Deed of Trust and Indian Trust Act, 1882 and General Financial Rules (GFR), 2017		
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? **(Indicate YES or NO)** *(Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)*	Yes (Rule 237 of GFR, 2017 are attached)		
6	If answer to SL No.5 above is **YES**, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December		
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned.	Annually		
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception **(Indicate YES or NO)**	Yes		
9	If answer to SL No. 8 above is **YES**, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2015-16, 2016-17 and 2017-18.	Year FY 2015-16 FY 2016-17 FY 2017-18	Lok Sabha 10.04.2017 02.04.2018 17.07.2019	Rajya Sabha 05.04.2017 28.03.2018 26.07.2019
10	If the answer to SL. No. 8 above is **NO**; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.	N.A.		

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

Statement Explaining Reasons for Delay Caused in Laying of Annual Accounts for the financial year ended on 31st March, 2019 on the Table of Parliament:

National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund) was incorporated on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed. As per the terms of the Trust Deed, NICDIT shall be subject to Audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The Annual Accounts of NICDIT for the financial year 2018-19 along with the copy of the resolution approving the Annual Accounts by the Board of Trustee were forwarded to the Office of C&AG vide letter dated 11th September, 2019 for taking up the audit.

The audit was conducted by an audit team deputed from the Office of C&AG from 10th October, 2019 till 18th October, 2019. Necessary explanations / clarifications were provided to the Audit Team during and after the course of Audit. The replies of the management to the Half Margins issued by the audit team were submitted on 7th November, 2019. The Draft Separate Audit Report on the Annual Accounts of NICDIT for the year ended on 31st March, 2019 was issued vide letter no. PDCA/ND/CHQ-II/27-17/2019-20/1143 dated 19th December, 2019. The reply to the Draft SAR was submitted to the office of C&AG on 10th January, 2020.

Since the Annual Report and Annual Accounts of NICDIT for financial year 2018-19 could not be laid on the table of Parliament during Winter Session, a request was made vide NICDIT letter Dated 20th November, 2019 for seeking time extension which was approved for laying the documents during Budget Session.

However, the final Separate Audit Report (SAR) by C&AG could be received on 13th March, 2020 and as per the requirement, before laying the same on table of the Parliament it is required to be placed before the Board of the Trustees of NICDIT.

The meeting of Board of Trustees scheduled on 31st March, 2020 could not be held because of the COVID pandemic and thereafter the onset of lockdown period. Finally, the meeting of the Board of Trustees could be held on 19th August, 2020 wherein the Board of Trustees took note of the Separate Audit Report issued by C&AG.

On the basis of the reasons cited above, the request for extension of time was made through DPIIT which was accorded till next (252) Session, 2020 of Rajya Sabha vide communication dated 1st July, 2020 from Additional Director, Rajya Sabha Secretariat.

In view of the above reasons, the Annual Accounts of the NICDIT for the Financial Year 2018-19 could not be laid on the table of the Parliament.

ANNUAL REPORT
(FINANCIAL YEAR 2018-19)

In accordance with the approval of Government of India on 15th September, 2011, DMIC Project Implementation Trust Fund was incorporated on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

The Government of India accorded approval for expanding the mandate and scope of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) by order dated 22nd December, 2016 and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. NICDIT will function under the administrative control of the Department for Promotion of Industy and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India . The Government has also approved constitution of a Board of Trustees of NICDIT with the following composition:

1. Secretary, DPIIT, Chairperson;
2. Secretary, Department of Expenditure, Member;
3. Secretary, Department of Economic Affairs, Member;
4. Secretary, Road Transport & Highways, Member;
5. Secretary, Shipping, Member;
6. Chairman, Railway Board, Member;
7. CEO, NITI Aayog, Member; and
8. CEO, NICDIT, Member Secretary

The role and functions of NICDIT are as follows:

a) Establishing an enabling institutional, financing and operational framework for the development of Industrial Corridors;

b) Considering proposals received from different state Governments/UTs for establishing new Industrial corridors, Nodes, Early Bird Projects and Standalone projects;

c) Appraising all project proposals and sanction of equity or loan or both to SPVs and grants for project development as per approved delegation of financial powers;

d) Supporting project development activities in Industrial Corridors through Knowledge Partner(s), Special Purpose Vehicles (SPV's) and State Governments and assisting States in identifying Anchor Investors for industries;

e) Raising funds as debt/equity as per requirement, leveraging resources provided by Government of India;

f) Entering into agreements with the State Governments/ Project specific SPVs/public or private organizations, as may be required from time to time. to give effect to the modalities outlined in previous paragraphs;

g) Providing funds for land acquisition through existing mechanisms of States for specifically identified Strategic Early Bird Projects which could be developed on PPP models. However, land for city / node development will necessarily be the equity of the State and will be acquired and fully paid for by them.

The Institutional Framework of NICDIT is as under:

a. The Board of NICDIT shall approve and sanction the optimal mix of debt and equity, choice of financial instruments, quantum of funds, terms and conditions and disbursement schedule from the grant provided by GoI, to the SPVs after taking into account inter alia, the progress of land acquisition and actual execution of works at each industrial city. Similarly, grant to knowledge partner(s) for project development will be given in phases as per progress of work.

b. NICDIT will leverage the resources provided by the Government of India to raise long-term funding from financial institutions and also, after obtaining due approvals, raise tax Free Bonds, Capital Gain Bonds, Credit Enhancement, etc. for supporting the development of Industrial Corridors.

c. GoI's contribution to NICDIT will be used as a revolving corpus. Investments into the SPVs by GoI will be routed through NICDIT so that all debt service payments by SPVs and proceeds from equity disinvestment from SPVs, including SPVs developed by DMICDC so far, by utilizing grants given by the GoI can be ploughed back into the Corpus, enabling NICDIT to undertake the development of more such industrial cities in future. The nodal / city level SPVs may further raise long-term debt finance through credit enhancement by appropriate guarantees from Government of India / State Government, so that it becomes viable for investment by insurance and pension funds. The nodal / city level SPVs will seek to employ innovative infrastructure funding and delivery tools such as user fee funding, pricing innovations, and delivery through various PPP arrangements. Funds raised by the State Government / SPVs as loans or otherwise also will count towards State's contribution.

d. For financial support to PPP projects, the extant guidelines for their Formulation, Appraisal and Approval as in Central Sector infrastructure projects shall be followed. Such projects would be eligible for Viability Gap Funding (VGF) in accordance with the prevalent policy. Secretary, DIPP and Member- Secretary, NICDIT will be members of the Public Private Partnership Approval Committee (PPPAC) for Industrial Corridor projects. In order to ensure coordinated development in consonance with the Master Plans / Development Plans, all proposals for VGF in the Industrial Corridors will be examined and recommended by NICDIT.

e. Each industrial city / node will be supported by GoI to an average of Rs.2500 crore subject to a maximum extent of Rs.3000 crore depending on the geographical location, size, contribution of the State and the development needs. The actual requirement may vary for each city / node, depending upon the cost of land and infrastructure development and the ability of the respective State Governments to mobilise financial resources for land procurement / land pooling. The State Government's contribution

will be by way of land or any other funds raised by it from any source including bi-lateral / multi-lateral funding. While the total requirement per city for non-PPP projects may be much larger and would vary from city to city, the above amount is being sought from the Government of India to trigger the first phase of development of these industrial cities / nodes. Subsequently, funds will be raised through internal monetization etc.

Delegation of Powers

NICDIT will appraise all proposals for non-PPP projects placed before it. Based on appraisal by NICDIT Board, it will approve projects valuing upto a sum of Rs. 300 crore as hitherto. Approval of Minister-in-charge will be obtained in case of projects valuing more than Rs. 300 crore and up to Rs. 500 crore. Proposals above Rs. 500 crore but upto Rs.1000 crore will be approved by the Minister-in-charge of Ministry of Commerce & Industry and Finance Minister. All proposals exceeding Rs. 1000 crore will be submitted to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for obtaining approval.

During the year 2018-19, meeting of the Board of Trustees cannot be held.

Planning of DMIC Nodes and their Sustainability Features adopted:

DMIC nodes under development adopts a sustainable approach that forms the ground work to aid the evolution of a Low Carbon City (LCC), including planning for Open green spaces, public transit and transit oriented development (TOD), encouraging the use of renewable energy, minimising the use of conventional energy, optimizing the conservation and recycling of water, and recovery and recycling of solid waste materials. Following are the key features of the Trunk infrastructure which are adopted in all nodes:

a) All Utilities are planned to be underground which leads to better usage of land.They are also outside the carriage way so that during maintenance and other works, the main carriageway is not affected.
b) The bus stations are planned within preferable walking distance of 400 m. Better last mile connectivity options provided to increase accessibility. Provision for Bus Bays/Bus Stops to minimize the effect on traffic.
c) Waste water will be collected and recycled from STP and CETP and redistributed to the City for non-potable purpose. SCADA system will be used to prevent any overflows and to maintain efficiency. Adoption of zero liquid discharge (ZLD) for sustainable solutions. Separate sewer lines for industrial and residential lines.
d) Conservation of water through rain water harvesting is adopted at city level. In Dholera for instance a 100-meter wide open channel with more than 2500 Million litres of capacity will be used for water harvesting, irrigation for parks and gardens as well as for non-potable purpose etc.
e) The entire infrastructure for Green field City is planned with SCADA, sensors and automation to generate real time information and to operate & manage it in efficient manner. This will facilitate Intelligent transport management, E-governance, Digital health & Education, Emergency and City operations.

f) Planning for Green spaces by categorization of hierarchy for open green spaces which are as follows:
    i. Neighbourhood parks within five minutes walking;
    ii. Community parks within Ten minutes walking;
    iii. Liner Park along the storm water canal within the city.
g) Planned for safe and sustainable Multi Modal Transportation System integrated with public transportation modes and non – motorized modes.
h) Planned electric charging stations at major transit interchanges with parking facilities in the clusters with social infrastructure.
i) All the lakes being improved and additional canals have been planned to increase the retention of water and also provide recreational area to the residents.
j) Wide sidewalks and cycle track for residents to walk from home and reduce pollution.
k) An extensive Web based GIS application for visualization of all plots and assets. A comprehensive online land management system for investors to get information, apply for land and follow their application through to allotment.

Overall Review of the Business and Operations

The salient features of the progress of projects at a glance is as under:

1. In case of DMIC project, the construction of trunk infrastructure related activities are in full swing at the following four locations:

    - Activation area for Dholera Special Investment Region in Gujarat admeasuring 22.5 sq. kms;
    - Phase-1 of Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra admeasuring 18.55 sq. kms;
    - Integrated Industrial Township Project at Greater Noida, Uttar Pradesh admeasuring 747.5 acres;
    - Integrated Industrial Township Project at Ujjain, Madhya Pradesh admeasuring approx. 1100 acres.

2. The land Allotment policies have been finalized. 2 plots in Dholera Special investment Region in Gujarat, 4 plots in Integrated Industrial Township in Uttar Pradesh, 1 plot in Integrated Industrial Township Vikram Udyogpuri in Madhya Pradesh and 56 plots in Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra have been allotted;

3. Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed for Krishnapatnam Node in Andhra Pradesh and Tumakuru Node in Karnataka and project SPV's have also been incorporated;

4. Apart from the above highlighted projects, project developmental activities are also being taken forward for the following projects:

- Mass Rapid Transit System (MRTS) Project from Gurgaon to Bawal in Haryana and Ahmedabad to Dholera in Gujarat;
- Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) Project, Nangal Chaudhary at Haryana;
- Multi Modal Logistics Hub (MMLH) and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Dadri, Uttar Pradesh;
- Multi Modal Logistics Park at Sanand in Gujarat;
- Greenfield International Airport Project at Dholera in Gujarat;
- Aerotropolis Project at Rajasthan.

The state-wise progress of DMIC Project is as under: -

GUJARAT

Dholera Special Investment Region (DSIR):

- Preliminary Engineering works for various trunk infrastructure components has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- SPV by the name of "Dholera Industrial City Development Limited" has been incorporated. State Govt. has transferred 2245.08 Ha to the SPV and matching equity has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust) amounting to Rs. 1294.23 crore;
- MoEF&CC has provided Environmental Clearance for Dholera Special Investment Region;
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Activation Area of Dholera for Rs. 2784.82 crore divided into five packages, the individual status is indicated as under:
  - EPC for Roads and Services Contract (INR 1,734 crore) awarded. L&T is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto July 2019 – 74.67%;
  - EPC for BEC Building Contract (INR 72.31 crore) awarded. Cube Construction Engineering Ltd. is the selected bidder and work is completed;
  - EPC for Water Treatment Plant (WTP) Contract (INR 90 crore) awarded. SPML is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto July 2019 – 65.00%;
  - EPC for Sewage Treatment Plant (STP) Contract (INR 54 crore) awarded. L&T is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto July 2019 – 47.66%;

- EPC for Central Effluent Treatment Plant (CETP) contract (INR 160 crore) awarded. L&T is the selected bidder and work is in progress; Physical progress upto July 2019 – 24.11%;

- ICT consultants have been appointed and the process of selection of Master System Integrator (MSI) is in progress;
- Land allotment policy has been finalized and 03 plots admeasuring 152.71 acres have been allotted with TATA Chemicals (126 acres) as the anchor investor;
- Road shows and round table conferences are being organized to create awareness and to attract anchor tenants/ investors.

Multi Modal Logistic Park (MMLP) at Sanand, Gujarat (500 acres):

- Techno-Economic Feasibility Study (TEFS) is being finalized by the Project consultants;
- The connectivity plan for the proposed project has been prepared and the same has been presented to the State Govt., DFCCIL & MOR for review and approval;
- Land is in the possession of the State Govt.;
- State Govt. has given concurrence on the Shareholder's agreement for formation of the SPV and the same has been placed for the consideration of NICDIT.

MRTS between Ahmedabad and Dholera, Gujarat:

- DPR for MRTS prepared and approved by the State Govt.;
- Project has been included in JICA Rolling Plan for DMIC Project;
- Land acquisition for the MRTS Project will be initiated as part of RoW of expressway project. DPR for Expressway Project between Ahmedabad and Dholera is being prepared by the consultant appointed by NHAI;
- NHAI has floated tenders for construction of four packages for the Expressway for entire stretch.

Greenfield International Airport at Dholera in Gujarat:

- Consortium of M/s PwC has been appointed as the Transaction Advisor;
- Environment Clearance has been obtained from MoEF&CC. Ministry of Civil Aviation has granted "in principle" clearance to the project;
- State Govt of Gujarat has agreed to make available 1426 Ha of land on lease rent of Rs. 1 per annum for 30 years further expandable to another 30 years;
- Board of AAI has approved DPR and the proposal of 51% equity participation in the project;
- Shareholders Agreement (SHA) was signed between AAI, Govt. of Gujarat & NICDIT on 25.03.2019;
- NICDIT as part of its equity (16%) has released Rs. 19.85 crore.

Bhimnath Dholera Rail Line Project:

- The Board of SPV-DICDL has approved the estimated cost of the project as finalised by Western Railways during the meeting held on 6th September, 2017;
- The project will be implemented by DICDL as per the Non-Govt. Railway (NGR) model of MoR. The project will be implemented as a joint venture between NICDIT and Govt. of Gujarat and project cost will be funded by 100% equity;
- Draft DPR report has been submitted by the consultant. The land acquisition plans have been finalized for area outside DSIR. Land acquisition has been initiated by DSIRDA.

MAHARASHTRA

Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA):

- Preliminary Engineering works for Phase-1 of SBIA (8.39 sq. kms) has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- Node/City level SPV by the name "Aurangabad Industrial Township Limited" (AITL) has been incorporated. State Govt. has transferred 8.39 sq kms to the SPV and the matching equity has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)) amounting to Rs. 602.80 crore;
- Environment Clearance for Shendra-Bidkin Industrial Area has been granted by MoEF&CC;
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Shendra Industrial Area for Rs. 1533 crore. Further the individual status of various packages is indicated as under:
  - EPC for Roads, Drains, Culverts, Water Supply, Sewerage and Power systems awarded (INR 656.89 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC Contractor. Physical progress upto July 2019 – 87.54%;
  - EPC for construction of Road over Bridges awarded (INR 69.45 crore). Patil Construction and Infrastructure Ltd is the EPC Contractor. Physical progress upto July 2019 – 78.62%;
  - EPC for District Administration Building (INR 129 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC Contractor. The works has been completed and the building is in use;
  - EPC for Sewerage Treatment Plant (STP), Common Effluent Treatment Plant (CETP) & Solid Waste Management (INR 72.52 crore). Passavant Energy is the EPC Contractor. Physical progress upto July, 2019 – 34.07%;
  - EPC for Landscape and Irrigation Works (INR 112 crore). Shapoorji Palloni is the EPC Contractor. Physical progress upto July, 2019 – 20.00%;
  - ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 142 crs). Honeywell is the selected agency. Physical progress upto July 2019 – 72.45%;
- Land allotment policy finalized and 56 plots have been allotted including industries in the Shendra Industrial Area. Hyosung Corporation is the First Anchor Investor in Shendra Industrial Area (land allotted – 100 acres);

- Project developmental activities for Bidkin are being taken forward and trunk infrastructure packages worth INR 6414.21 crore have been approved by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) [formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)] and subsequently by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA);
- State Govt. has transferred 1376.81 Ha to the project SPV for Bidkin Industrial Area and matching equity has been released amounting to INR 1149.90 crore;
  - L&T has been appointed as the EPC Contractor (INR 1223 crore) for Bidkin Phase-1 i.e. 10 sq. kms for roads and underground utilities/services & work is in progress. Physical progress upto July 2019 – 87.10%;
  - ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 142 crs). KEC is the selected agency. Physical progress upto July 2019 – 9.00%.

Dighi Port Industrial Area:

- State Govt. has acquired the land for phase-1 i.e. 3000 Ha.
- M/s Egis has been appointed for carrying out Detailed master planning and preliminary engineering activities.

MADHYA PRADESH

Pithampur Dhar Mhow Investment Region:

State Support Agreement (SSA) and Shareholder's Agreement (SHA) has been executed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT), and State Govt. of Madhya Pradesh/MPTRIFAC for node/city level.

Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain:

- Land admeasuring 1100 acres has been transferred to the project SPV and the matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- The agreement on "Supply of water from Water supply pipeline from Ujjayini to Ujjain to Industrial area Vikram Udyogpuri Ltd. in Ujjain" has been signed between with Narmada Valley Developm ent Authority (NVDA) and Vikram Udyogpuri Ltd. to meet the water requirement of the project.
- AECOM, the Program Management Consultants is supervising the construction related activities;
- A consortium of SPML and OM Metals, the EPC Contractor is undertaking the implementation of various trunk infrastructure components. Physical progress of works upto July 2019 – 93.00%;
- Land allotment policy has been finalized and 01 plot admeasuring 12 acres have been allotted to AMUL. The total committed investment is Rs. 200 crores;
- Road shows and round table conferences have been organized to create awareness and attract investors.

Water Supply Project for Pithampur Industrial Area:

- SPV by the name of DMIC Pithampur Jal Prabandhan Company Limited (DMIC PJPCL) has been incorporated between State Govt. and National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Project cost of INR 306.55 crore has been approved and matching equity of INR 17.15 crore has been released by Trust;
- L&T has been appointed as the EPC contractor for Rs. 219 crore and work has been completed;
- NICDIT has approved the proposal submitted by the Govt. of M.P. to acquire 49% equity share holding of NICDIT in DMIC Pithampur Jal Prabandhan Ltd.

HARYANA

Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary:

- Land admeasuring approx. 886 acres has been identified in District Mahendergarh for the project;
- The project SPV has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- The master planning for the project has been completed and approved by the State Govt.;
- CCEA has approved the project with financial sanction of Rs. 1029.49 crores for development of Phase I and "In-Principle" approval for development of Phase II of the project;
- State Govt. has transferred. 639 acres out of the total land and equity amounting to Rs. 191.67 crore has been released by NICDIT;
- State Environment Appraisal Committee Environment (SEAC) has recommended the project to State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for Environment Clearance;
- State Govt. is moving forward with the acquisition of remaining land parcels;
- The project has been posed for debt funding from Asian Infrastructure Investment Board (AIIB) to NICDIT.

Mass Rapid Transit System (MRTS) Project:

- State Government has approved the Final DPR;
- Project SPV has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- Land is in possession of the State Govt.;
- The project has been included in the JICA Special Rolling Plan for DMIC Project.

UTTAR PRADESH

Integrated Industrial Township Project at Greater Noida:

- Preliminary engineering activities have been completed and SPV by the name of "Integrated Industrial Township Greater Noida Limited" has been incorporated;
- Land admeasuring 747.5 acres has been transferred to the Project SPV and the matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Shapoorji Pallonji has been appointed as the EPC Contractor for INR 426 crore for undertaking the implementation of various trunk infrastructure components and work is in progress. Physical progress of work upto July 2019 – 97.00%;
- SIEMENS has been appointed as EPC Contractor for INR 121 Crore in Jan-2018 for power distribution works within the site. Physical progress of work upto July 2019 – 72.00%;
- Land allotment policy finalized and 152 acres of land allotted to 4 applicants with Haier (123.4 acres) as the anchor investor;
- Road shows and round table conferences were organized.

Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida:

- The SPV for Integrated Industrial Township Project will be implementing the MMLH and MMTH project as well;
- Detailed Project Report (DPR) is under preparation;
- Discussions have also been initiated with DFCCIL so as to provide connectivity to the site from Western and Eastern DFC;
- Memorandum of Understanding has been approved by Indian Railways and will be executed shortly;
- Project proposal was considered by NICDIT in its last meeting and was approved subject to availability of 80% land for a cost of 4034 cr. including land;
- State Govt. has communicated that 80% land has been acquired and accordingly the project proposal has been placed for the recommendation of NICDIT;
- The project has been posed for debt funding from Asian Infrastructure Investment Board (AIIB) to NICDIT.

RAJASTHAN

Khushkhera Bhiwadi Neemrana Investment Region, Rajasthan:

- Master Plan has been notified;
- Land acquisition process has been initiated by State Government;
- Rajasthan Special Investment Region Act has been notified by State Government for enabling execution of SHA & SSA;

Greenfield International Airport at Rajasthan:

- Site Clearance accorded by MoCA;
- The Detailed Project Report (DPR) has been submitted by Airport Authority of India (AAI).

- The Terms of Reference (TOR) for carrying out the EIA study for the proposed Bhiwadi International Airport, District Alwar, Rajasthan has been issued by the MoEF&CC vide letter dated 17th August, 2017. The public hearing was held on 12th September 2018. The Expert Appraisal Committee (EAC) of MoEF&CC in its meeting held on 17.01.2019 considered and reviewed the application for Grant of Environment Clearance for the project;
- Airport Authority of India has submitted Final DPR and the same is being reviewed by the State Govt.

Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA):

- Master Plan has been notified;
- State Govt. has been requested to expedite the land acquisition.
- The Environment Clearance for the Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA) project in Rajasthan has been granted by the MoEF&CC .

SMART COMMUNITY PROJECTS:

A) Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- The 05MW Solar Power Plant has been commissioned on 03rd September, 2015. The power is feeding to State Grid (i.e. 220KV GSS Neemrana) at the agreed tariff of Rs. 8.77/- per unit as per the Power Purchase Agreement (PPA) with NVVN Limited.
- The Power Purchase Agreement (PPA) for 01MW Micro Grid Solar Power Plant has been executed with MIKUNI India Private Limited on the basis of fixed tariff of Rs. 11.99/- per unit for the period of 10 years on 17th May, 2016.
- Generation of power from 01MW Micro Grid Solar Power Project for feeding high quality, stable and renewable green power to MIKUNI India Private Limited has started from 10th July 2017.

B) Logistic Data Bank Project:

- Operations initiated at JNPT Port with effect from 01st July, 2016 and new port terminal namely Bharat Mumbai Container Terminal at JNPT port with effect from 01st April 2018.
- Operations have also been successfully launched across all container terminals at APSEZ Mundra (Adani Port Special Economic Zone) & AHPPL Hazira (Adani Hazira Port Pvt. Ltd) in Gujarat from 01st May, 2017;
- More than 18 million containers have been tagged/de-tagged till 20th August 2019;
- To expand LDB services at pan India level the agreements have been signed with Tuticorin Port Trust, Visakhapatnam Port Trust, Chennai Port Trust, Mormugao Port Trust, Paradip Port Trust, Mumbai Port Trust, New Mangalore Port Trust, Kattupalli Port Private Limited, Krishnapatnam Port, Ennore Port Limited, Kolkata Port Trust, Halida, Cochin Port Trust.

OTHER PROJECTS:

India International Convention and Expo Centre (IICC) at Dwarka, Delhi:

- Cabinet has accorded its approval and Project Steering Committee has been constituted to steer the project;
- SPV for the project has been formed in the name of India International Convention and Exhibition Centre Limited.
- Possession of land has been taken over from DDA by DIPP;
- AECOM has been appointed as Programme Management Consultants to undertake various project development activities;
- L&T has been appointed as EPC contractor for the development of Phase 1 components (Rs. 2791 cr.), Physical progress of works upto July 2019 – 53.60%;
- DMRC has taken over the possession of remaining 0.1368 Ha land parcel after making due payment to the land owners on 18th July, 2018.
- Other project development activities are being taken forward in consultation with stakeholders like Delhi Development Authority (DDA), Airport Authority of India (AAI), Delhi Jal Board (DJB), Delhi Transco Limited (DTL), National Highways Authority of India (NHAI) etc.;
- Memorandum of Understanding has been signed with DMRC for extension of Airport Express Line to IICC Project and construction work is going on in full swing;
- AAI has given its "No Objection Certificate" on the Building Heights proposed for the project;
- South Delhi Municipal Corporation (SDMC) has granted approval on the building layout and Delhi Fire Services has granted NOC on the building layout plans for phase – 1 development;
- HVPNL & BSES Rajdhani Power Ltd. have completed the work of shifting of HT Lines which were passing through the site;
- Regular review meetings are being held to monitor the progress of the project;
- Boston Consulting Group has been appointed as Commercialization, Planning & Transaction Advisor and a consortium of IDOM (Spain) & CP Kukreja Architects has been appointed as Preliminary Engineering and Architectural Consultants;
- A consortium of Korea International Exhibition Centre and eSang Networks Company Ltd. has been appointed as the Operator for Exhibition and Convention Centre and Operator Services Agreement for a term of 20 yrs;
- IDBI Capital Markets & Securities Ltd. has been appointed as Financial Advisor for raising loans;
- Foundation Stone Laying Ceremony was performed on 20th September 2018 by Hon'ble Prime Minister of India;
- National Council for Cement and Building Materials has been appointed for Consultancy Services for "Third Party Quality Assurance and Audit" (TPQA);
- A term loan amounting to Rs. 2150.16 crore has been finalized from SBI with the approval of Board of IICC;
- MoU Agreement between BSES Rajdhani Power Ltd (BRPL) & IICC for Bulk power supply to IICC Dwarka was signed on 14th January 2019.

OTHER INDUSTRIAL CORRIDORS:

A. CHENNAI BENGALURU INDUSTRIAL CORRIDOR (CBIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed and three nodes have been identified for development:
  i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh;
  ii. Tumakuru, Karnataka; and
  iii. Ponneri, Tamil Nadu.

i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed and project SPV by the name of 'NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited' has been incorporated on 07th August, 2018.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities for the Activation Area (2500 acres) have been finalized and project proposal is placed for the consideration of NICDIT.
- Letter of Award to L&T has been issued for consultancy services for Environmental Impact Assessment;

ii. Tumakuru, Karnataka:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed and project SPV i.e. CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd. has been incorporated on 1st November, 2018.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities for the Activation Area (1736 acres) have been finalized and project proposal is placed for the consideration of NICDIT.

iii.Ponneri, Tamil Nadu:

- For Ponneri node in Tamil Nadu, State Govt. has given their concurrence on the Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA). The same is placed for the consideration of NICDIT.

B. AMRITSAR KOLKATA INDUSTRIAL CORRIDOR (AKIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed and seven Industrial Manufacturing Clusters (IMCs) have been identified for development under phase-I. These IMCs are Rajpura-Patiala (Punjab), Gohna (Haryana), Prag-Khurpia Farms (Uttakakhand), Bhaupur (Uttar Pradesh), Gamhariya (Bihar), Barhi (Jharkhand) and Raghunathpur (West Bengal);
- Concept Master Plans for all the identified IMCs have been finalized;
- The respective State Govt(s). are in the process of acquiring land for Rajpura-Patiala (Punjab), Gohna (Haryana), Prag-Khurpia Farms (Uttakakhand), Bhaupur (Uttar Pradesh), Gamhariya (Bihar), and Barhi (Jharkhand) IMCs.

i. Raghunathpur, West Bengal

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is being finalized with the state government.
- Land parcel of 2483 acres is under the possession of State Govt. of West Bengal.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are in progress;

Awards and recognitions for Smart cities under DMIC Project

Dholera Smart City:

1. Geospatial Excellence Award, March 2016
2. Bentley "Be Inspired", March 2016
3. IGBC Green City Rating "Platinum", Sept 2016
4. Best City for Integrated Planning, Feb 2017
5. Best Green City, Feb 2017
6. Best Innovative Greenfield Industrial Township Project, Feb 2019

AURIC Smart City:

1. Auric Hall - 2017 Times National award for Best office building and Best in Architecture
2. 2018 National Safety Council 2nd Place for Infra Project 3.2 Million safe Manhours
3. 2018 Skoch Order-of-Merit Award for E-Land Management System
4. 11 EBJ/CCBJ Awards for Environmental and Climate Change Innovations in San Fransico received award for Technology Merit: Smart Cities.

- **Technology Merit: Smart Cities:** Extended Aurangabad Industrial Smart City project, integrating smart technologies and next-level infrastructure to transform AURIC (Aurangabad Industrial City) into a smart, green industrial city of the future.

FINANCIAL RESULTS SUMMARY

During the Financial Year 2018-19, a sum of Rs. 998.52 crore and Rs. 98.48 crore was released by GOI towards the Main Corpus and Additional Corpus of the Trust, respectively.

The Financial Summary of the Trust at the end of the financial year is as follows:

(Rs. in crore)

Particulars	Financial Year 2018-19 (Audited)	Financial Year 2017-18 (Audited)
Corpus / Capital Fund*	4740.06	3727.00
Fixed assets	Nil	Nil
Investments	4421.60	3473.62
Current Assets	318.51	253.51
Earmarked Funds*	Nil	Nil
Current Liabilities	0.06	0.13
Non-Current Liabilities	Nil	Nil
Gross Income	28.88	13.53
Excess /(Deficit) of Income over Expenditure	17.06	(1.59)

Auditors

As per Clause 13 of the Trust Deed, the NICDIT shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The President of India entrusted the audit of Accounts of NICDIT to the office of C&AG for a period of 5 years from the year 2017-18 to 2021-22 under section 20(1) of the Comptroller & Auditor General (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971.

During the year, the C&AG Audit Team conducted Annual Accounts Audit and Transaction Audit for the financial year 2017-18.

The approved Annual Accounts of the NICDIT for the Financial Year 2018-19 have been audited by the office of C&AG.

Particulars of Employees

NICDIT has no employees during the year 2018-19.

In accordance with the clause 8.5 of the Trust Deed, Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) shall act as Chairman of the Trust and CEO & MD, DMICDC Limited shall act as Chief Executive Officer ("CEO") of NICDIT.

Acknowledgement

The Chief Executive Officer of the Trust wishes to place on record, his gratitude to all Trustees for their continued support, co-operation and contribution in the Trust.

***For* National Industrial Corridor Development and Implementation Trust**

(K.Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

Place : New Delhi
Date : 19-Aug-2020

संख्या / No.

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated

सेवा में ,

सचिव,भारत सरकार ,
वाणिज्य एवं उधोग मत्रालय,
उधोग भवन,
नई दिल्ली

विषय- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखाओ पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट के वर्ष 2018-19 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

हस्ता0
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

संख्या:- PDCA| ND\CHQ-I|27-17|19-20| 928 दिनाँक:- 13 3.2020

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट अध्यक्ष, कमरा संख्या-341 तीसरी मंजिल, होटल अशोक, नई दिल्ली-110021 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

प्राची
13.3.20
(प्राची पाण्डेय)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2019

We have audited the attached Balance Sheet of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (Trust) as at 31 March 2019 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) entrustment letter No.1 (27)-B(R)/2013 dated 1 September 2014. These financial statements are the responsibility of the Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust as required under clause 13.1 of the Deed of Trust dated 27 September 2012 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

Grants-in-aid

Status of Grants-in-aid under Project Implementation Fund and Project Development Fund was as under (as per information furnished by Management):

(₹ in crore)

Particulars	**Project Implementation Fund (For creation of capital assets)**	**Project Development Fund (to carry out project development activities)**
Opening Balance	28.36	0.02
Add :Grants received during 2018-19	998.52	98.48
Add: Interest and Dividend earned during 2018-19	13.68	0.50
Add: Loan repayment by DMICDC Neemrana Solar Power Co. Ltd.	1.10	-
Add: Loan repayment by DMICDC Logistics Data Services Ltd.	6.00	-
Add: Income tax refund	6.36	2.04
Add: Reimbursement of Expenses	57.21	-
Total amount available	**1111.23**	**101.04**
Less:- Amount utilised	1009.87	101.00
Closing Balance as on 31.03.19	101.36	0.04

(v) We report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a) In so far as it is related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust as at 31 March, 2019 and

b) In so far as it related to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Prachi Pandey 13.3.20

(Prachi Pandey)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-I,
New Delhi

Place: New Delhi

Dated: 13 March 2020

Annexure

(to Separate Audit Report on the Accounts of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2019)

1. **Adequacy of Internal Audit System**

   Internal Audit for the year 2018-19 has been conducted by a Chartered Accountancy firm.

2. **Adequacy of Internal Control System**

   Internal control system is commensurate with the size of the organisation.

3. **System of Physical Verification of Fixed Assets**

   Trust is not having any fixed assets.

4. **System of Physical Verification of Inventory**

   Trust is not having any inventory.

5. **Regularity in payment of statutory dues**

   Trust is generally regular in payment of statutory dues.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

BALANCE SHEET
as at 31st March, 2019

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2018-19	2017-18
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Fund	1	47,40,05,82,863	37,26,99,54,627
Reserves and Surplus	-	-	-
Earmarked / Endowment Funds	-	-	-
Loans and Borrowings	-	-	-
Current Liabilities and Provisions	2	5,72,110	12,67,341
Total		**47,40,11,54,973**	**37,27,12,21,968**
ASSETS			
Fixed Assets	-	-	-
Investments	3	44,21,60,25,101	34,73,61,72,881
Current Assets, Loans, Advances etc.,	4	3,18,51,29,872	2,53,50,49,087
Total		**47,40,11,54,973**	**37,27,12,21,968**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form an integral part of this Balance Sheet.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Member Secretary

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 30-Aug-2019

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

for the year ended 31st March 2019

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2018-19	2017-18
INCOME			
Interest Earned	5	26,59,97,977	13,23,35,360
Other Income	6	2,27,55,993	29,79,496
Total (A)		**28,87,53,970**	**13,53,14,856**
EXPENDITURE			
Other Administrative Expenses	7	11,81,25,734	15,12,06,393
Total (B)		**11,81,25,734**	**15,12,06,393**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)		17,06,28,236	(1,58,91,537)
Transfer to Additional Corpus		51,20,754	1,50,80,947
Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being Surplus / (Deficit) carried to Main Corpus / Capital Fund		**16,55,07,482**	**(3,09,72,484)**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form an integral part of this Balance Sheet.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Member Secretary

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 30-Aug-2019

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

RECEIPTS AND PAYMENTS

for the year ended 31st March 2019

(Amount - ₹)

RECEIPTS	2018-19	2017-18	PAYMENTS	2018-19	2017-18
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in Hand	-	-	Other Administrative Expenses	11,86,20,965	15,02,92,802
b) Bank Balances					
i) In Saving Accounts	97,29,855	16,48,662	**II. Payments made for various projects**		
ii) In Deposit Accounts	27,41,20,456	6,70,70,29,237	a) Out of Main Corpus		
			Release of loan to:		
II. Grants Received			i) DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	-	3,60,00,000
a) From Government of India for Main Corpus	9,98,51,74,213	8,01,37,00,000	ii) DMIC Vikram Udyogpuri Limited	50,00,00,000	1,32,54,00,000
b) From Government of India for Additional Corpus	98,48,25,787	-	b) Out of Additional Corpus		
			- Release of Grant-in-aid to DMICDC Ltd.	1,01,00,00,000	87,55,27,000
III. Income on Investments from					
a) Main Corpus	45,33,641	-	**III. Investments and deposits made**		
b) Additional Corpus	-	-	a) Out of Main Corpus	9,47,96,52,220	11,65,01,74,881
IV. Interest Received			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-progress**	-	-
a) On Bank Deposits (net of TDS)	10,56,92,135	2,63,82,982			
b) On Saving Accounts	12,68,395	1,86,53,546			
c) On Loans and Advances (net of TDS)	1,20,70,743	2,06,87,765	**V. Refund of Surplus money/Loans**	-	-
V. Other Income			**VI. Finance Charges (Interest)**	-	-
a) Main Corpus	1,38,18,374	25,15,742			
b) Additional Corpus	44,03,978	4,63,754	**VII. Other Payments**		
			Expenses incurred for SPVs	-	-
VI. Amount Borrowed	-	-	Expenses incurred for IICC Ltd	-	57,20,82,739
VII. Any Other Receipts					
Repayment of Loan by:			**VIII. Closing Balances**		
(i) DMICDC Neemrana Solar Power Co. Ltd.	1,10,00,000	6,64,89,756	a) Cash in Hand	-	-
(ii) DMICDC Logistics Data Services Ltd.	6,00,00,000	-	b) Bank Balances		
Income Tax Refund	8,40,21,438	3,31,05,504	i) In Saving Accounts	1,03,179	97,29,855
Reimb. of expenses incurred for IICC Ltd.	57,20,82,739	26,50,785	ii) In Deposit Accounts	1,01,39,65,390	27,41,20,456
Total	**12,12,27,41,754**	**14,89,33,27,733**	**Total**	**12,12,27,41,754**	**14,89,33,27,733**

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Member Secretary

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 30-Aug-2019

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2019

(Amount - ₹)

Particulars		2018-19	2017-18
SCHEDULE 1 : CORPUS / CAPITAL FUND			
1.0. MAIN CORPUS / CAPITAL FUND			
Balance at the beginning of the year		37,23,97,74,984	29,30,18,90,510
Add: Contribution received towards Corpus / Capital Fund		9,98,51,74,213	8,01,37,00,000
Add / (Less): Interest relating to PDF relating to earlier years accounted for as PIF now rectified		-	(11,43,042)
Add / (Less): Balance of net income / expenditure transferred from the Income and Expenditure Account		16,55,07,482	(3,09,72,484)
Add / (Less): Amount transferred to Additional Corpus*		-	(4,37,00,000)
Balance at the year end (A)		**47,39,04,56,679**	**37,23,97,74,984**
1.1. ADDITIONAL CORPUS FOR DMICDC LIMITED			
Balance at the beginning of the year		2,29,26,00,000	2,24,89,00,000
Add: Contribution towards Additional Corpus / Capital Funds		98,48,25,787	-
Add: Amount transferred from Main Corpus*		-	4,37,00,000
	(a)	3,27,74,25,787	2,29,26,00,000
Add: Balance of net income / expenditure transferred from Income and Expenditure Account			
- During the Previous Years		37,63,06,643	36,00,82,654
Add / (Less): Interest relating to PDF relating to earlier years accounted for as PIF now rectified		-	11,43,042
- During the Current Year		51,20,754	1,50,80,947
	(b)	38,14,27,397	37,63,06,643
	(a) + (b)	**3,65,88,53,184**	**2,66,89,06,643**
Less: Amount utilised by releasing Grant-in-aid to DMICDC Ltd.			
- During the Previous Years		2,63,87,27,000	1,76,32,00,000
- During the Current Year		1,01,00,00,000	87,55,27,000
	(c)	3,64,87,27,000	2,63,87,27,000
Balance at the year end [B = (a) + (b) - (c)]		**1,01,26,184**	**3,01,79,643**
Grand Total (A + B)		**47,40,05,82,863**	**37,26,99,54,627**

* Amount received from Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) towards non-recurring Grant for creation of Capital Assets for transferring these funds to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited for undertaking pre-project activities of Exhibition-cum-Convention Centre Project at Dwarka, New Delhi. Accordingly, funds were transferred to DMICDC Limited against pre-project expenses of Exhibition-cum-Convention Centre Project at Dwarka, New Delhi.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2019

(Amount - ₹)

Particulars		2018-19	2017-18
SCHEDULE 2 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
2.0. CURRENT LIABILITIES			
1. Sundry Creditors:			
(a) For Goods		-	-
(b) Others		1,28,610	9,47,341
2. Statutory Liabilities			
(a) Others			
- Tax Deducted at Source (TDS)		8,500	5,000
	(A)	1,37,110	9,52,341
2.1. PROVISIONS			
1. Others			
(a) Provision for Audit fees			
- Current Year		1,70,000	1,50,000
- Previous Years		2,65,000	1,65,000
	(B)	4,35,000	3,15,000
Total (A + B)		**5,72,110**	**12,67,341**
SCHEDULE 3 : INVESTMENTS			
1. Investment From Earmarked / Endowment Funds		-	-
2. Investment - Others			
(a) Shares			
- Investment in Equity Shares of Pithampur Jal Prabandhan Co. Ltd.		17,15,00,000	17,15,00,000
- Investment in Equity Shares of Vikram Udyogpuri Ltd.		55,93,00,000	55,93,00,000
- Investment in Equity Shares of Integrated Industrial Township Greater Noida Limited		6,17,20,00,000	6,17,20,00,000
- Investment in Equity Shares of Aurangabad Industrial Township Ltd.		17,52,70,00,000	14,52,70,00,000
- Investment in Equity Shares of Dholera Industrial City Dev. Ltd.		17,45,54,08,351	12,94,22,74,881
- Investment in Equity Shares of DMICDC Logistics Data Services Ltd.		4,01,98,000	4,01,98,000
- Investment in Equity Shares of DMIC Haryana Global City Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- Investment in Equity Shares of DMIC Haryana MRTS Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- Investment in Equity Shares of DMIC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited		1,96,67,18,750	5,00,00,000
- Investment in Equity Shares of Dholera International Airport Co. Ltd.*		4,39,00,000	4,39,00,000.00
- Investment in Equity Shares of CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.		2,50,00,000	-
- Investment in Equity Shares of NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited		2,50,00,000	-
(b) Others			
- Release of Funds to DMICDC Limited for Investment in Equity Shares of M/s DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited (Refer Note No. 3 of Schedule-9)		13,00,00,000	13,00,00,000
Total		**44,21,60,25,101**	**34,73,61,72,881**

* As per the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), NICDIT in its 2nd meeting held on 23rd August, 2017 approved transfer of 43,90,000 number of Equity Shares of Dholera International Airport Company Limited at a face value of Rs.10/- each held in the name of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) to National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) during the financial year 2017-18.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2019

(Amount - ₹)

Particulars		2018-19	2017-18
SCHEDULE 4 : CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC			
4.0. CURRENT ASSETS:			
1. Bank Balances with Scheduled Banks:			
(a) On Deposit Accounts			
- Main Corpus		1,01,36,10,390	27,39,85,456
- Additional Corpus		3,55,000	1,35,000
(b) On Saving Accounts			
- Main Corpus		50,818	96,89,202
- Additional Corpus		52,361	40,653
	(A)	**1,01,40,68,569**	**28,38,50,311**
4.1. LOANS, ADVANCES & OTHER ASSETS:			
1. Loans and Advances:			
To DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited		2,50,00,000	3,60,00,000
To DMICDC Logistics Data Services Limited		6,75,00,000	12,75,00,000
To DMIC Vikram Udyogpuri Limited		1,82,54,00,000	1,32,54,00,000
2. Interest Accrued on Deposits with Bank:			
Main Corpus		45,75,903	81,66,889
Additional Corpus		115	2,967
3. Interest Accrued on Loans and Advances:			
From DMIC Vikram Udyogpuri Limited		17,65,09,309	5,24,80,593
4. Others:			
Tax Deducted at Source			
- Main Corpus		6,22,74,769	9,94,62,984
- Additional Corpus		98,01,207	3,00,99,869
Other Loans and Advances*		-	57,20,85,474
	(B)	**2,17,10,61,303**	**2,25,11,98,776**
Total (A + B)		**3,18,51,29,872**	**2,53,50,49,087**

* Include:

(i) Rs. 52,20,82,739/- received from Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) formerly Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) vide sanction order no. P-40019/4/2017-ID-I(Part) dated 6th March, 2018 for transferring these funds to India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC) for meeting the expenditure of Exhibition cum Convention Centre Project at Dwarka, New Delhi and the same has been replenished by IICC Limited to NICDIT on 3rd April, 2018; and

(ii) Rs. 5,00,00,000/- transferred to IICC Limited on behalf of Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) vide letter no. P-40022/67/2017-ID-I dated 08.12.2017 towards the initial paid-up share capital of IICC Limited and the same has been replenished by DPIIT to NICDIT vide sanction order no. P-40019/4/2017-ID-I(Part) dated 11th May, 2018.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

NOTES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
for the year ended 31st March 2019

(Amount - ₹)

Particulars	2018-19	2017-18
SCHEDULE 5 : INTEREST EARNED		
(1.) On Term Deposits (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	11,28,82,992	2,24,36,155
[TDS for Current Year - ₹ 1,12,88,345/- (Previous Year - ₹ 22,36,235/-)]		
(b) Additional Corpus	6,24,969	1,46,02,569
[TDS for Current Year - ₹ 1,24,054/- (Previous Year - ₹ 14,62,881/-)]		
(2.) On Savings Accounts (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	11,76,588	1,86,38,922
(b) Additional Corpus	91,807	14,624
(3.) On Loans:	15,12,21,621	7,66,43,090
[TDS for Current Year - ₹ 1,51,22,162/- (Previous Year - ₹ 76,64,310/-)]		
Total	**26,59,97,977**	**13,23,35,360**
SCHEDULE 6 : OTHER INCOME		
Interest on Income Tax Refund:		
(a) Main Corpus	1,38,18,374	25,15,742
(b) Additional Corpus	44,03,978	4,63,754
Dividend Income	45,33,641	-
Total	**2,27,55,993**	**29,79,496**
SCHEDULE 7 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
Service Fees	11,77,62,257	15,04,58,063
Auditors Remuneration		
- Current Year	1,70,000	1,65,000
- Previous Years	5,320	60,640
Advertising Expenses	-	2,25,277
Expenses on Filling Fees	9,743	1,11,990
Professional and Consultancy Fees	94,000	68,800
Meeting and Conference Expenses	19,411	1,11,837
Prior Period Expenses	35,000	-
Others		
- Misc. Expenses	30,003	4,786
Total	**11,81,25,734**	**15,12,06,393**

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the basis of accrual method of accounting unless otherwise stated.

2.0 Long-term Investments

Long-term investments are shown at actual cost including the cost incidental to acquisition.

3.0 Fixed Assets

3.1 Fixed Assets are shown at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

3.2 Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the assets are ready for use, as intended by the management;

3.3 Subsequent expenditures relating to Fixed Assets are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these assets will flow to Trust and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Income and Expenditure Account when incurred;

3.4 Depreciation is provided on pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) method. Depreciation is provided based on useful life of the assets.

4.0 Government Grant

4.1 Trust receives non-recurring / recurring grants-in-aid from Government of India separately for:

(i.) "Creation of Capital Assets" towards the main Corpus of the Trust shown as "Main Corpus" under "Corpus / Capital Fund"; and

(ii.) "General" earmarked to be given to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited as grant-in-aid to carry out project development activities shown as "Additional Corpus" under "Corpus / Capital Fund".

This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

4.2 The grants-in-aid received from the Government of India are accounted on receipt basis.

5.0 Revenue Recognition

5.1 Income is recognised on accrual basis.

5.2 Interest earned on surplus funds of "Main Corpus" and "Additional Corpus" are shown distinctly under these respective heads. This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

6.0 Other Administrative Expenses

Other administrative expenses are met out of the interest income on surplus funds of grant-in-aid received under the head "Main Corpus / Capital Fund".

7.0 Service Fees

Service Fees for the services rendered by DMICDC Limited @ 1% (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore in a year) of the funds released by Trust to various projects out of Project Implementation Fund (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

8.0 Foreign Currency Transactions

Expenses in foreign currency / transactions are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

9.0 Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Income and Statement account on accrual basis.

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1.0 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier DMIC Project Implementation Trust Fund) was formed on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) vide order no. 11/1/2016 dated 22.12.2016 conveyed the approval of Government of India in its Cabinet Meeting held on 7th December, 2016 for the expansion of mandate of Trust to include other Industrial Corridors i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC), Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC), Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and Vizag – Chennai Industrial Corridor (VCIC) Projects along with existing Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project and its redesignation as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT).

2.0 As per the Financial and Institutional structure for the development of industrial cities in the Delhi - Mumbai Industrial Corridor (DMIC) approved by the Government on 15th September, 2011, the Government of India will provide a grant-in-aid of ₹ 17,500 crore to the Trust over the next 5 years beginning 2011-12, for the development of industrial cities. An Additional Corpus of ₹ 1000 crore would be given to Trust for passing on to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited as grant-in-aid over the next five years to carry out project development activities and to form project specific SPVs and sectoral holding companies consisting of project specific SPVs in a range of infrastructure areas.

Government of India in its meeting held on 7th December, 2016 accorded its permission to utilise the above approved financial assistance along with additional sanctioned amount of ₹ 1584 crore (i.e., ₹ 1500 crore for other industrial corridor and ₹ 84 crore for Administrative expenses of NICDIT) within the extended period upto 31st March, 2022.

During the year, a sum of ₹ 998.52 crore (Previous Year ₹ 801.37 crore) was received towards Main Corpus / Capital Fund and ₹ 98.48 crore (Previous Year Nil) towards the Additional Corpus for passing on to DMICDC Limited.

The Government of India's contribution to Trust would be used as a Revolving Corpus.

3.0 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to DMICDC Limited out of Main Corpus/ Capital Funds of Trust during the financial year 2013-14 for onward release to its 100% owned SPV namely "DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited" towards 100% equity investment of Trust through DMICDC Limited for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through DMICDC Limited. The amount so released was reduced from the Corpus Funds of Trust during the F Yr 2013-14.

As per the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountant of India obtained on the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) regarding the disclosure of the transaction, the amount reduced from the Main Corpus /Capital Fund of the Trust has been added back during the financial year 2016-17.

The corresponding disclosure has been made under the head "Investment".

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

4.0 Employees Benefits

Trust does not have any employee. The provision for liability on account of employees' benefit including retirement benefit is Nil (Previous Year NIL).

5.0 Contingent Liabilities

The Contingent Liability of Trust is NIL (Previous Year NIL).

6.0 Capital Commitments

The Capital Commitment of Trust is NIL (Previous Year NIL).

7.0 Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management and to the best of their knowledge and belief, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business which would not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

8.0 Taxation

The Director of Income Tax (Exemption) vide order dated 13th August, 2013, has granted registration under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act, 1961 with effect from the assessment year 2013-14 in response to an application filed by Trust on 28th March, 2013. Accordingly, the Trust has not made provision for income tax.

		Amount (₹) 2018-19	Amount (₹) 2017-18
9.0	**Foreign Currency Transactions**		
9.1	Earning in Foreign Currency	Nil	Nil
9.2	Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
10.0	**Remuneration to Auditors**		
10.1	Audit Fees		
	- For Current Year	1,70,000	1,65,000
	- For earlier Financial Years	5,320	60,640
10.2	For Taxation Matters	-	-
10.3	For Other Services	-	-

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS
for the year ended 31st March 2019

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

11.0 Project Development Expenditure

In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the Annual Accounts of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred by DMICDC Limited out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

As per the directions of the Board of Trustees, 'Project Development Expenditure' incurred by DMICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid, to the concerned subsidiaries /SPVs has been transferred to the respective SPVs and the recovery of the same has been deferred till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.

Further, in accordance with the accounting policies of DMICDC Limited, the project development expenditure incurred for the projects which have not been taken off or no further activities have been carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). /Nodal Agency(ies) does not provide for such recovery, have been disclosed as reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' in the Financial Statements of DMICDC Limited.

12.0 Receipts and Payments Account

The Receipts and Payments Account is prepared on the basis of inflows and outflows of cash during the year. This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

13.0 Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

14.0 Schedules 1 to 9 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2019 and the Income and Expenditure Account for the period ended on that date.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Alkesh Kumar Sharma)
CEO & Member Secretary

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 30-Aug-2019